RNI No. : CHHHIN/2011/40280

पाक्षिक पत्रिका

छत्तीसगढ़ आजतक

वर्ष : 11 • अंक : 12 • फरवरी - द्वितीय 2022 • मूल्य : 30/-

छत्तीसगढ़ गढ़ रहा
शिक्षा का नया इतिहास

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से लेकर संविधान की रचना करने वालों तक का यह सपना रहा है कि उच्च स्तरीय शिक्षा देश के प्रत्येक बच्चे को सुलभ होगा. पहले-पहल तो सरकारी स्कूलों ने अच्छा काम किया पर समय के साथ शिक्षा व्यापार बन गया और यह निजी हाथों में चला गया. साधन संपन्न लोगों के बच्चे निजी स्कूलों में जाते रहे और सरकारी स्कूल धीरे-धीरे मध्यान्ह भोजन केन्द्र बनकर रह गए. छत्तीसगढ़ सरकार धारा के विपरीत तैरने की कोशिश कर रही है. यह रास्ता कठिन अवश्य है पर असंभव नहीं है.

भिलाई को विकास के दौड़ में अग्रणी रखने
वाले कुशल सेवक, आधुनिकता के साथ
ही सामाजिक सौहार्द के सूत्रधार विधायक

मान. देवेन्द्र यादव जी

को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं

मनोज राजपूत
कांग्रेस नेता

सुमित सिंह पवार
जिला महामंत्री - भिलाई शहर कांग्रेस कमिटी

MANOJ RAJPUT
LAYOUTS PVT. LTD.

10

छत्तीसगढ़ गढ़ रहा शिक्षा का नया इतिहास

07

आदिवासी अंचल के किसान पूछ रहे कहां है अपना पम्प?

आदिवासी अंचल के लगभग साढ़े पांच हजार किसान आज भी सरकारी बोरवेल की बाट जोह रहे हैं. केन्द्र प्रवर्तित "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई...

समान शिक्षा पर असमान गुणवत्ता

वर्तमान में शासन का 'समान शिक्षा' का रोडमैप दूर की कौड़ी साबित हो रही है. शासन प्रत्येक जिले के कई....

20

30

उग रहे खण्डहर के टापू

अपनी क्रमवार बसाहट और हरियाली के लिए मशहूर भिलाई कभी देश का औद्योगिक तीर्थ कहलाता था....

ओबीसी आरक्षण : किसने मारी कुण्डली

केन्द्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में ओबीसी को आरक्षण तो मिला है पर उन्हें नौकरियां नहीं मिल पाई हैं. नतीजा यह है कि प्राध्यापक पद के स्वीकृत 313 पदों में से केवल 9 पर ही नियुक्तियां हो पाई हैं. स्वयं सरकार ने लोकसभा में स्वीकार किया है कि 55 फीसद आरक्षित पद रिक्त पड़े हैं. दरअसल किसी को उनकी पड़ी ही नहीं है...

04

तिल-तिल बढ़ रहा सोमनाथ का शिवलिंग

श्रीराम और माता सीता यहां शिवनाथ और खारून के संगम के आसपास टहला करते थे. संगम की रेत से प्रभु श्रीराम ने शिवलिंग का निर्माण किया...

33

08

परदेशी प्रेम से लुटिया डूबी भाजपा की

भाजपा की पंद्रह साल की सरकार को कांग्रेस ने सत्ता से बाहर कर दिया. छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान को सामने रखकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनीति को नई दिशा दी है. अब इसके परिणाम सामने आने लगे हैं. "छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया" का नारा अब राजनीति के गलियारे में सूत्र वाक्य बन गया है. राज्य के स्वाभिमान...

38

ग्राम सड़क योजना का अनाथों जैसा हाल

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की हालत अनाथों जैसी हो गई है. वह जिये या मरे इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. सड़कों के नाम पर कई मालामाल हो गए पर सड़कें कुपोषित ही रह गईं. इनमें से कुछ ने तो समय से पहले ही दम तोड़ दिया. पांच साल तक संधारण की शर्त में बंधा होने के बाद...

संपादकीय, विज्ञापन, प्रसार कार्यालय
ब्लॉक बी-1, प्रथम तल, बॉम्बे मार्केट, रायपुर (छ.ग.)
492001 फोन : 0771-4221384

संपादक लखन लाल

सलाहकार संपादक सादात अनवर

विशेष प्रतिनिधि मंजुला कौशिक । विक्रम जनबंधु विजय प्रताप कश्यप

कानूनी सलाहकार गिरीशचंद्र शर्मा

प्रतिनिधि : •**रायपुर**-भूपेन्द्र वर्मा •**दुर्ग**-रामशरण कौशिक •**पाटन**-महेश शर्मा •**भिलाई**-श्यामलाल साहू •**भिलाई-3**-सतीशदास वैष्णव •**राजिम**-राजेन्द्र भारती •**राजनांदगांव**-राहुल गौतम •**कबीरधाम**-सुरेश प्रसाद गुप्ता •**कोरबा**-गेंदलाल शुक्ला •**जांजगीर चांपा**-समयदास अविनाशी •**कटघोरा**-विकास जायसवाल •**कोण्डागांव**-सुरेश पाटले •**नारायणपुर**-नरेन्द्र देवांगन •**जगदलपुर**-हेमंत कश्यप •**धमतरी**-जियाऊल हुसैनी •**बलौदाबाजार**-संतोष यादव •**तिल्दा नेवरा**-दिलीप वर्मा •**बोड़ला**-नवलकिशोर श्रीवास्तव •**बिलासपुर**-राजन कुमार सोनी •**धरसींवा**-देवेन्द्र वर्मा •**अंबिकापुर**-धनंजय दुबे •**मनेन्द्रगढ़**-मनप्रीत सिंह साहनी •**रामानुजगंज**-विकास केसरी •**वाड्रफनगर**-नितेश श्रीवास्तव •**दल्लीराजहरा**-झुनमुन गुप्ता •**गुण्डरदेही**-रमेश चांडक

सरगुजा प्रभारी अमरेश्वर दुबे
मार्केटिंग एवं फोटो जर्नलिस्ट पी. मोहन

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक- लखन लाल के लिए सागर प्रिंटर्स, पुरानी बस्ती, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित एवं ब्लॉक बी-1 प्रथम तल, बॉम्बे मार्केट, रायपुर (छ.ग.) से प्रकाशित, **संपादक - लखन लाल**

सर्वाधिक सुरक्षित : किसी भी रूप से सामग्री की नकल प्रतिबंधित है. सभी विवादों का निपटारा रायपुर न्यायालय में होगा.

लखन लाल

संपादकीय

रेत से सोना बनाने में माहिर रेत माफिया

रेत से सोना बनाने के खेल में छत्तीसगढ़ की रेत माफिया माहिर है. रेत की कालाबाजारी न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि सीमावर्ती राज्य उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड और उधर महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश में भी बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है. कभी सस्ती बिकने वाली रेत आजकल सोने के भाव में बिकती है. अब तो रेत तस्करी के इस खेल में इंसानों का खून भी मिल गया है जिससे उसके भाव आसमान छूने लगे हैं. पिछली भाजपा सरकार ने रेत के माफियाओं को खुली छूट दे दी थी. शायद यही वजह है कि भाजपा राज में रेत माफिया ने दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की. उन्हें इस बात की भी छूट थी कि उनके भाजपा शासन तंत्र में जो कोई उनके रास्ते में आए उन्हें निर्दयता और बेरहमी के साथ रास्ते से हटा दिया जाए. शासन, प्रशासन का यह आलम था कि जो भी राह में रोड़ा बने उन्हें फर्जी मुकदमे लगाकर जेल के सींखचों के पीछे धकेल दिया जाए. आज भी ऐसे बहुत से लोग अपनी स्थिति पर बार-बार आँसू बहा रहे हैं जिन्होंने ईमानदारी के साथ भ्रष्ट तंत्र को बदलने का प्रयास किया है.

यह भी जांच का विषय है कि सरगुजा और उसकी नदियों से रेत माफिया ने बिना नंबर की गाड़ियों से, ट्रैक्टर ट्रालियों से कैसे रेत उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के बिल्डरों तक पहुंचायी. ऐसा नहीं है कि रेत माफिया कुख्यात बिल्डर ही हैं. अनेक सफेदपोश लोग भी इसमें शामिल हैं. ये लोग रातों रात अमीर बनने के चक्कर में रेत की इस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं. न केवल रेत माफिया बल्कि उनके गुर्गे भी सफेदपोश बनकर इस तस्करी में लिप्त हैं. इनके हाथ पुलिस, शासन-प्रशासन, विधायक, मंत्री, पंच, सरपंच आदि जनप्रतिनिधियों तक जा पहुंचे हैं. इनकी मिलीभगत से छत्तीसगढ़ की रेत से भरी नदियां खाली हो रही है. यह भी अन्वेषण का विषय है कि क्या रेत की तस्करी से नदियां सूख रही है? आखिर रेत प्रति ट्रक 6000 रु. कौन अदा करता है? यदि छत्तीसगढ़ रेत की तस्करी का गढ़ बन गया है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है?

एक बात तो साफ है कि प्रशासनिक संरक्षण या साझेदारी के बिना कोई भी विधि विरुद्ध अवैध कारोबार कभी फलफूल नहीं सकता. अवैध खनन माफिया और संबंधित विभागों के अधिकारियों की मिलीभगत के कारण ही अवैध उत्खनन पर रोक लगाना संभव नहीं हो रहा. यह इस बात की ओर भी संकेत है कि शासन-प्रशासन में बैठे लोग अपने कार्यकर्ताओं और मतदाताओं की आवाज को अनसुना कर केवल चांदी के खनकते सिक्कों की आवाज ही सुनना चाहते हैं, जो उनकी तिजोरी भर सकें. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को लेकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. इसका असर बस्तर, सरगुजा और महाराष्ट्र की सीमा में देखने को मिल रहा है. अधिकारियों ने अब रात दिन एक कर दिया है. वे रात-रात भर जागकर अवैध उत्खनन से भरी गाड़ियों को जब्त कर रहे हैं. इसके साथ ही रेत के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है. रेत विक्रेताओं का आरोप है कि जाँच के नाम पर स्थानीय पुलिस, माइनिंग और राजस्व विभाग के अफसर जुर्माना और चालानी कार्रवाई कर रहे हैं. इसकी वजह से उन्हें अतिरिक्त शुल्क देना पड़ रहा है. इसकी वजह से रेत के दामों में अतिरिक्त बढ़ोत्तरी हो रही है. रेत के खनन और परिवहन को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद रेत के दाम अचानक बढ़ गए.

अब तक 600 फिट हाइवा भर्ती में जिस रेत के लिए 10,500 तक देने पड़ रहे हैं. वहीं रेत 15,500 रुपये तक भी बिकी है. राज्य में रेत की कीमत एक समान नहीं रही. कुछ जगहों पर 500 से 600 फिट रेत के दाम 10 से 12 सौ रु. तक थे. यह भी जांच का विषय है कि जिलों में रेत के दाम नियंत्रित कौन कर रहा है. क्या बाजारवाद को इस बात की छूट दे दी गई है कि वह जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्य अपनी मनमर्जी के अनुसार बढ़ाएं? दरअसल, मुख्यमंत्री की सोच के अनुरूप कोई भी पहल तभी कारगर सिद्ध हो सकती है जब सत्ता, संगठन और प्रशासन तीनों मिलकर साहस और निष्पक्षता के साथ कड़े कदम उठाए. जनता की आवाज को पूरी तरह अनदेखा न कर पूरी संवेदनशीलता के साथ सरकारी तंत्र को जनसरोकर से जोड़ने की दिशा में सार्थक पहल की जाए.

रेत माफिया पर शिकंजा

रेत माफिया के खिलाफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संज्ञान कब, क्यूँ और कहाँ लिया ये तो वही बेहतर बता सकते हैं. अलबत्ता अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का समय निकट आ गया है. निश्चित ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चाहते हैं कि नदी की संपदा अक्षुण्ण रहे; उसकी जलधारा सतत् प्रवाहमान रहे और नदी के तटीय क्षेत्र को कटाव का खामियाजा न भुगतना पड़े. सफेद कालरों से प्रदेश की नदी को सुरक्षित रखा जा सकें. यदि 'सफेद कॉलरों' को जेल की सींखचों के पीछे न पहुंचाया गया तो छत्तीसगढ़ की जनता एक और अपराध को घटित होते हुए देखती रहने को मजबूर रहेगी.

बहने दो नदी को

मानव समाज, सरकार, सामाजिक संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं को वर्तमान परिवेश में यह समझने की आवश्यकता है कि नदी की प्रकृति, उसके स्वभाव, उसकी प्रवृत्ति, प्राकृतिक क्षेत्र को समझते हुए उसके साथ कार्य करना होगा. तब ही नदियां स्वच्छ सुंदर वह जैव विविधता से परिपूर्ण होने के साथ ही हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो सकेंगे.

नदी, सदियों से सदा प्रवाहमान जलधारा है. शिवनाथ नदी, खारून नदी, महानदी और गंगा, यमुना आदि सभी नदियों की धारा मानव जीवन को एक नया आयाम देती हैं. यही कारण है कि नदी के तट पर ही शहरों की बसाहट है, यानि कि यह कहा जा सकता है कि नदी के किनारे पर ही मानव सभ्यता विकसित होती है.

नदी सामान्यतः दो शब्दों से न + दी से मिलकर बना जिसका अर्थ सदा नीर देने वाली होता है अर्थात नदी हमेशा पानी देने वाली होती है. ये हमेशा ऊंचे से नीचे, पर्वत से मैदान, झील से समुद्र की ओर वर्षा जल या बर्फ के पानी का बहता हुआ स्रोत है. नदी को समझने के लिए स्वाभाविक विभिन्न प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होना तय है. आखिर नदी क्या है? नदी से क्या लाभ? नदी का हमारे जीवन में क्या योगदान? आदि अनेक प्रश्न ही नहीं विचार भी उत्पन्न होते हैं, जिसके लिए इसकी प्रकृति व प्रवृत्ति को जब तक नहीं समझ जाएं समझ पाना बड़ा मुश्किल होगा.

नदी का वर्गीकरण जल प्रवाह, वर्षा की मात्रा, वनस्पति, भौगोलिक संरचना, क्षेत्र वहां के पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर करता, ये सभी नदी की बहाली को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं. नदी को जैसा कृष्ण गोपाल व्यास द्वारा लिखित पुस्तक " ताकि नदियां बहती रहे", में परिभाषित किया गया है कि "प्रकृति द्वारा निर्मित एवं अपने पथ पर लगातार बहते पानी की धारा ही नदी है". इससे नदी को समझना बहुत सरल होगा.

नदी जैसे मानव शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना है, उसी प्रकार से नदी विभिन्न छोटी-छोटी नालियों के आपस में जुड़ने से बनी प्राकृतिक संरचनाओं में से एक है. बहुत सी छोटी नदियां मिलकर एक बड़ी महानदी का निर्माण करती है, भारत में लगभग दो सौ नदियां हैं, जिनमें गंगा प्रवाह सबसे बड़ा व सिंधु नदी लम्बाई में सबसे बड़ी है. वहीं लगभग ग्यारह सौ ऐसी नदी है जो दस से पच्चास किलोमीटर दूर तक जाकर लुप्त हो जाती हैं या अपनी सहायक नदी का हिस्सा बन जाती, इनमें कई नदियां अपना नाम भी नहीं रख पाती. लेकिन नदी का बड़ा या छोटा होना महत्व नहीं रखता, नदी का मानव जीवन में योगदान, उपयोगिता, जैवविविधता, पर्यावरण संरक्षण में सहयोग उससे ज्यादा महत्व रखता है. नदी की अपनी महत्त्वाकांक्षाओं से क्षेत्र विशेष के लोगों, वन्यजीव, जलीय जीव के विकास में योगदान से लगाया जा सकता है.

नदी को परिभाषित होने के बाद नदी की आवश्यकता को समझना बहुत आवश्यक है, भूगर्भिक जल के संतुलन बनाने व संरक्षण में नदियों की अहम भूमिका होती है. नदी अपने प्रवाह क्षेत्र में वर्षा जल को उसके ढाल के साथ बहाव क्षेत्र में बहाकर ले जाने के साथ भू-जल संरक्षण का कार्य करती है और यह कार्य तब तक करती रहती है जब तक भूगर्भिक जल का दोहन बंद नहीं हो जाएं व नदी के पेटे में पानी ऊपरी हिस्से से एक्विफरों से डिस्चार्ज होकर मिलना बंद नहीं हो.

वर्षा काल में पानी के साथ बहती हुई नदी के पानी की कुछ मात्रा धरती के नीचे मौजूदा एक्विफरों में जमा होता है यही भूजल पुनर्भरण है. नदी जल भूजल भंडारों का निर्माण करता है, भूजल पुनर्भरण के प्रभाव से भूजल स्तर ऊपर उठता है. नदी में पानी जब तक बहता रहता है, तब तक भूजल भरण की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहतीं तथा वर्षा बंद होने के बाद एक्विफरों में जमा पानी स्थिर नहीं होता वह ऊंचे स्थानों से नीचे स्थानों की ओर बहता रहता है, भूजल का ऊपरी स्तर नदी तल के ऊपर तब आता है जब तक वह नदी में डिस्चार्ज होता उसके नदी में डिस्चार्ज होने तक नदी अविरल बहती रहती है, यह ईश्वरीय (प्राकृतिक, कुदरती) देन है.

धरती की कोख का पानी नदी तल पर दिखाई देने तक ही नदी अविरल रहती है. उसका पानी स्वच्छ व निरापद रहता है. उसके स्वच्छ रहने की क्षमता बनी रहती है. जलीय जीव सुरक्षित व फलते-फूलते अपना दायित्व निभाते है. तभी जैव विविधता से परिपूर्ण रहती है. वहीं जलीय जीव वनस्पति को बढ़ावा देने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण का कार्य करती है. प्राकृतिक आपदाओं से बचाने में सहायक सिद्ध होती हैं.

नदी प्राकृतिक संतुलन, जैव विविधता, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, भूगर्भिक भंडारों के रिचार्ज के लिए आवश्यक है. उसी प्रकार से नदी की स्वच्छता, बहाव क्षेत्र में उत्पन्न बाधाएं जो नदी को स्वतंत्र बहने से रोकने का कार्य कर रही, उन्हें दूर करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना नदी की जैव विविधता को बनाए रखना महत्वपूर्ण. मानव समाज, सरकार, सामाजिक संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं को वर्तमान परिवेश में यह समझने की आवश्यकता है कि नदी की प्रकृति, उसके स्वभाव, उसकी प्रवृत्ति, प्राकृतिक क्षेत्र को समझते हुए उसके साथ कार्य करना होगा. तब ही नदियां स्वच्छ सुंदर वह जैव विविधता से परिपूर्ण होने के साथ ही हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो सकेंगे.

ओबीसी आरक्षण

किसने मारी कुण्डली

केन्द्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में ओबीसी को आरक्षण तो मिला है पर उन्हें नौकरियां नहीं मिल पाई हैं. नतीजा यह है कि प्राध्यापक पद के स्वीकृत 313 पदों में से केवल 9 पर ही नियुक्तियां हो पाई हैं. स्वयं सरकार ने लोकसभा में स्वीकार किया है कि 55 फीसद आरक्षित पद रिक्त पड़े हैं. दरअसल किसी को उनकी पड़ी ही नहीं है. सरकार आरक्षण की घोषणा करके खुश है. इनके हित में न तो लोकसभा में कोई आवाज उठती है और न ही विधानसभा में. अकेला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) मुद्दे को जीवित रखे है. केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों में प्रोफेसर के लगभग सभी पदों पर सवर्ण कुण्डली मारे बैठे हैं.

» भूपेन्द्र वर्मा

उच्च शिक्षा के पदों में एससी/एसटी/ओबीसी आरक्षण को लेकर देशव्यापी आक्रोश भ्रम पर टिका हुआ है. हकीकत यह है कि आरक्षण का लाभ आज भी इस वर्ग को न के बराबर ही मिल पाया है. केन्द्रीय विश्वविद्यालयों एवं तकनीकी तथा शोध संस्थानों में 55 फीसद ओबीसी पद आज भी रिक्त पड़े हैं. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरू में ओबीसी कोटे के 89.8 फीसद पद रिक्त हैं.

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने एक लिखित जवाब में लोकसभा को बताया कि ये सभी स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं, इसलिए पदों को भरने की जवाबदारी भी उनकी ही है. उन्होंने बताया कि नियुक्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सरकार 12 जुलाई, 2019 को केन्द्रीय शिक्षण संस्थान (शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण) अधिनियम पारित किया है. जून 2019 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दिये हैं.

मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 तक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में ओबीसी के 50 फीसद से अधिक पद रिक्त थे.

आंकड़ों की मानें तो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी प्राध्यापकों के 313 पद हैं. यूजीसी के आंकड़े बताते हैं कि अगस्त 2020 तक इनमें से केवल 9 (2.8 फीसद) पद ही भरे जा सके थे. आंकड़े यह भी बताते हैं कि 1 जनवरी 2020 तक जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक भी ओबीसी प्राध्यापक नहीं था.

उच्च शिक्षा में ओबीसी अभ्यर्थियों की सर्वाधिक (60 फीसद) नियुक्तियां सहायक प्राध्यापक के पदों पर हुई है. सहायक प्राध्यापकों के लिए आरक्षित 2,232 में से 1,327 पद ही भरे जा सके हैं. ओबीसी एसोसिएट प्रोफेसर के 735 में से केवल 38 (5.17 फीसद) पद ही भरे जा सके हैं.

यह आंकड़े इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि केन्द्र सरकार "क्रीमी लेयर" को पुनः परिभाषित करने जा रही है. वेतनभोगी कर्मचारियों का वेतन इसका एक प्रमुख अवयव होगा. इसके आधार पर सीलिंग तय की जानी है. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) के साथ-साथ स्वयं भाजपा के अनेक ओबीसी सांसद इसका विरोध कर रहे हैं. इनका मानना है कि इससे ओबीसी पदों पर नियुक्ति की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी.

एनसीबीसी का मानना है कि ओबीसी अभ्यर्थियों को पदोन्नति से रोकने का प्रयास सभी स्तरों पर किया जा रहा है. यही कारण है कि सहायक प्राध्यापक के रूप में तो भर्तियां हो रही हैं पर उनके आगे बढ़ने के रास्ते में रुकावटें डाली जा रही हैं. ऐसा कई वर्षों से हो रहा है पर सरकार हस्तक्षेप नहीं कर रही.

इसलिए हो रहा विलम्ब

जेएनयू के प्राध्यापक नरेन्द्र कुमार ओबीसी के खाली पड़े पदों की तीन वजहें बताते हैं. उनका कहना है कि चयन एवं भर्ती प्रक्रिया काफी लंबी होती है. इन विश्वविद्यालयों में ओबीसी आरक्षण काफी विलम्ब से प्रारंभ हुआ. इसलिए यह प्रक्रिया वक्त ले रही है. इसके अलावा एक दिक्कत और है, विचारधारा. यदि आप किसी एक विचारधारा के पोषक नहीं है तो आपकी नियुक्ति कठिन हो सकती है.

यूजीसी के इस फैसले ने किया नुकसान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2016 के नियुक्तियों में ओबीसी को मिल रहे 27 फीसद आरक्षण को समाप्त कर दिया था. यह निर्देश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था. यूजीसी ने कहा था कि यह आरक्षण केवल सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति पर ही लागू होगी. इसके ऊपर के पदों पर कोई आरक्षण नहीं होगा.

प्रावधान हुए लागू पर नतीजे सिफर

12 जुलाई, 2019 को केन्द्रीय शिक्षण संस्थान (शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण) अधिनियम लागू किया गया. इसके तहत

1 अप्रैल 2018 तक ओबीसी पदों पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति आंकड़ों में

प्रोफेसरों की नियुक्ति

प्रोफेसर	कुल नियुक्त संख्या	न्यूनतम प्रतिशत	रिक्त पद
दलित	39 (3.47%)	15%	169
आदिवासी	6 (0.7%)	7.5%	84
पिछड़ा वर्ग	0 (0.0%)	27%	304
सवर्ण	1071 (95.2%)	50%	562

एसोसिएट प्रोफेसरों की नियुक्ति

एसोसिएट प्रोफेसर	कुल नियुक्त संख्या	न्यूनतम प्रतिशत	रिक्त पद
दलित	130 (4.96%)	15%	393
आदिवासी	34 (1.3%)	7.5%	197
पिछड़ा वर्ग	0 (0.0%)	27%	707
सवर्ण	2434 (92.9%)	50%	1310

सहायक प्राध्यापकों की स्थिति

असिस्टेंट प्रोफेसर	कुल नियुक्त संख्या	न्यूनतम प्रतिशत	रिक्त पद
दलित	931 (12.2%)	15%	1161
आदिवासी	4423 (5.46%)	7.5%	587
पिछड़ा वर्ग	1,113 (14.38%)	27%	2090
सवर्ण	5,130 (60.27%)	50%	3870

केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों तथा केन्द्र पोषित संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की सीधी भर्ती का प्रावधान किया गया. इससे ओबीसी पदों के लिए उच्च शिक्षा के उच्च पदों पर नियुक्ति का रास्ता तो खुल गया पर इसका कोई असर होना अभी बाकी है.

दलीलों में दम नहीं

उच्च शिक्षा के उच्च पदों पर ओबीसी के रिक्त पदों के बारे में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का कहना है कि योग्य अभ्यर्थियों के नहीं मिलने के कारण ही ये पद रिक्त हैं. एनसीबीसी का कहना है कि इन दलीलों में दम नहीं है. देश भर में इन विश्वविद्यालयों को क्या एक भी ऐसा

अन्य केन्द्रीय संस्थानों में नियुक्तियां एक नजर में

विभाग	कुल नियुक्त संख्या	पिछड़े	सवर्ण
रेलवे	16381	1,319 (8.05%)	11,273 (68.72%)
71 केन्द्रीय विभाग	3,43,777	51,384 (14.94%)	2,16,408 (62.95%)
एचआरडी मंत्रालय	665	56 (8.42%)	440 (66.17%)
केबिनेट सचिव	162	15 (9.26%)	130 (80.25%)
राष्ट्रपति सचिवालय	130	10 (7.69%)	97 (74.62%)

ओबीसी अभ्यर्थी नहीं मिला जिसे प्राध्यापक का पद दिया जा सके. दरअसल उच्च शिक्षा के केन्द्रीय संस्थानों में बैठे मठाधीश नहीं चाहते कि कोई ओबीसी उनकी बराबरी में बैठे. सूत्रों का मानना है कि शिक्षण संस्थान ओबीसी के लिए आरक्षित पदों को भरने में कोई दिलचस्पी नहीं लेते. इन पदों के लिए शायद ही कभी कोई विज्ञापन जारी किया गया हो. दिल्ली विश्वविद्यालय की चयन प्रक्रिया से जुड़े सुबोध कुमार बताते हैं कि तकरीबन सभी विश्वविद्यालयों की शीर्ष पदों पर सवर्णों का कब्जा है. शायद ही कोई ओबीसी कभी कुलपति बना हो.

आदिवासी अंचल के लगभग साढ़े पांच हजार किसान आज भी सरकारी बोरवेल की बाट जोह रहे हैं. केन्द्र प्रवर्तित "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" के तहत 2021 तक हर खेत को पानी पहुंचाया जाना था. 2019 में इस योजना का श्रीगणेश हुआ. सर्वे हुआ, कार्ययोजना भी बनी पर सिंचाई विभाग फाइल पर कुण्डली मारे बैठा है. तीन साल बीतने के बाद भी नतीजा सिफर है. किसानों के खेत सूखे के सूखे हैं. यह स्थिति तब है जब राज्य में किसानों की सरकार है और कृषि मंत्री स्वयं किसान हैं.

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लगा पलीता

अब भी प्यासे हैं आदिवासियों के खेत

सिंचाई विभाग की टेबल पर धरी रह गई फाइल

बनने थे 660 सफल पम्प, एक का भी पता नहीं

आदिवासी अंचल के किसान पूछ रहे कहां है अपना पम्प

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देश के आदिवासी बहुल वनांचलों के लिए ही बनाई गई है. इन अंचलों में सिंचाई की सुविधाएं न के बराबर हैं. सरकार की मंशा सिंचाई सुविधा देकर आदिवासी अंचल के किसानों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करना है. इसके लिए विस्तार से योजना बनाई गई है. योजना के तहत जहां-जहां विद्युत कनेक्शन नहीं हैं, वहां सोलार पैनल के जरिए इन पम्पों को संचालित किया जाएगा.

अकेले छत्तीसगढ़ की ही बात करें तो पूरे बस्तर संभाग में सिंचाई के लिए दुधावा, परलकोट और कोसारटेढ़ा के नाम से तीन सिंचाई बांध है जो सिंचाई की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है. छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत कांकेर जिले के सात और राजनांदगांव जिले के तीन विकासखण्डों को शामिल किया गया है.

योजना के तहत कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर, नरहरपुर, चारामा, कांकेर, अंतागढ़, कोइलीबेड़ा एवं दुर्गूकोंदल के 3959 किसानों को लाभान्वित किया जाना था। इसी तरह राजनांदगांव जिले के मानपुर, मोहला और छुरिया विकासखण्डों के 1445 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा. परन्तु अवधि समाप्त होने तक यहां काम शुरू भी नहीं हो पाया है. मोहला विकासखण्ड के सोमाटोली गांव के बिंदे सिंह कुंजाम, परगोंदी के मुरहाराम, दुर्गकोंदल के डोगरा गांव के रजभन, धनेसरा गांव के सगे सिंह बताते हैं कि उनके लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं थी. उन्होंने सोचा था कि अब डटकर खेती-किसानी करेंगे. जीवन स्तर बेहतर होगा, बच्चे पढ़-लिख लेंगे. पर हुआ कुछ नहीं और देखते देखते 3-4 साल निकल गए. वह तो भला हो केन्द्र सरकार का कि योजना की कछुआ चाल को देखते हुए इसकी मियाद 2026 तक बढ़ा दी गई है. अब एक बार फिर उम्मीद जागी है.

सवाल यह है कि राज्य में किसानों की सरकार है. कृषि मंत्री रविंद्र चौबे स्वयं किसान हैं. बस्तर क्षेत्र के 12 विधायक सत्तारूढ़ कांग्रेस से हैं. बावजूद इसके इस लाभकारी योजना के क्रियान्वयन में किसी ने रुचि नहीं ली. कागजी खानापूर्ति के बाद से योजना ठंडे बस्ते में पड़ी है. सिंचाई विभाग ने इस योजना पर युद्धस्तर पर काम क्यों नहीं किया, इसका जवाब मांगा जाना चाहिए. बता दें कि आदिवासी अंचलों के 90 प्रतिशत किसान अब तक सिंचाई सुविधा से वंचित हैं.

बस इतना सा था काम

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सिंचाई सुविधा विहीन आदिवासी क्षेत्रों में 660 सफल नलकूप बनाए जाने थे. इसका मतलब ऐसे नलकूपों से है जिसमें से कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त पानी प्राप्त किया जा सके. राजनांदगांव जिले में 178 तथा कांकेर जिले में 482 नलकूप बनाए जाने थे. इसके लिए नलकूप विभाग ने 63 करोड़ 86 लाख रुपए का प्रस्ताव बनाकर सिंचाई विभाग को सौंप दिया था. पर सिंचाई विभाग इसपर कुण्डली मारे बैठा है.

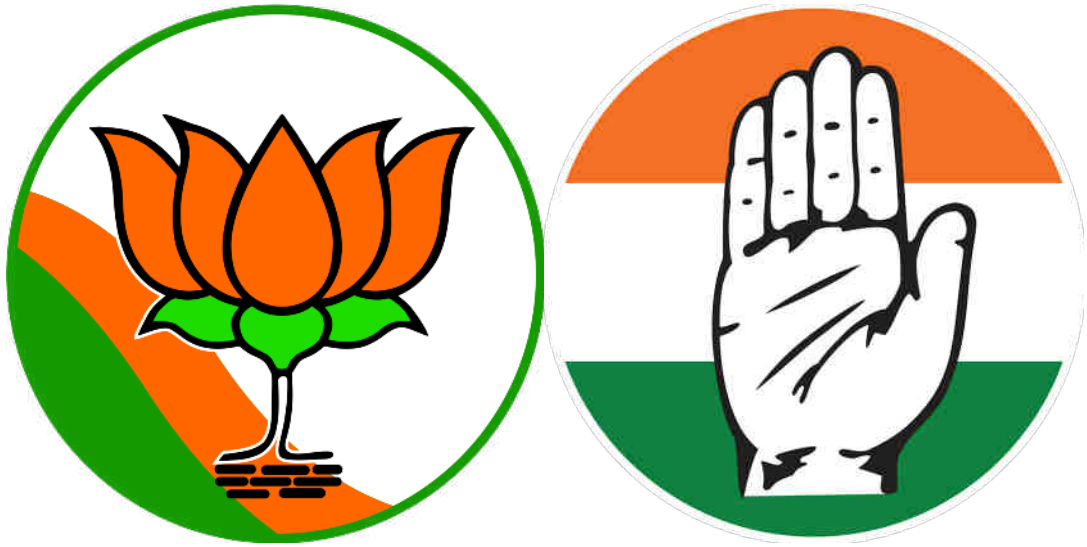

परदेशी प्रेम से

लुटिया डूबी भाजपा की

भाजपा की पंद्रह साल की सरकार को कांग्रेस ने सत्ता से बाहर कर दिया. छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान को सामने रखकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनीति को नई दिशा दी है. अब इसके परिणाम सामने आने लगे हैं. "छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया" का नारा अब राजनीति के गलियारे में सूत्र वाक्य बन गया है. राज्य के स्वाभिमान का प्रश्न उठाकर भूपेश बघेल ने जिस छत्तीसगढ़ियावाद की नींव रखी है, उस पर अब शानदार इमारत खड़ी हो गई है. इसके बाद प्रदेश में जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस ने इसी नीति के तहत भाजपा को बुरी तरह पछाड़ दिया है.

» प्रमोद अग्रवाल

राज्य का मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पंद्रह साल लगातार सत्ता में रहने के बाद भी सिर्फ तीन वर्ष के भीतर हाशिये पर चली गई. भूपेश सरकार की यह सबसे बड़ी विशेषता रही कि उसने पंद्रह साल सरकार चलाने वाले नेतृत्व की फेस वैल्यू समाप्त कर दी. भाजपा के पास आज छत्तीसगढ़वाद का कोई जवाब नहीं है. राज्य में भाजपा का नेतृत्व आज भी उन्हीं हाथों में है जिसे जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव में बुरी तरह नकार दिया था.

भाजपा में शुरू से ही छत्तीसगढ़ी नेताओं की उपेक्षा की जाती रही है. राज्य में भाजपा

छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान ने कांग्रेस का लौटाया मान

का शीर्ष नेतृत्व हमेशा यही चाहता रहा है कि यहाँ के सभी बड़े भाजपा नेताओं में चाहे कितना भी मतभेद रहा हो, इस मुद्दे पर वे सभी हमेशा सहमत रहे कि लोकल नेतृत्व को न उभरने दिया जाए. कुशाभाऊ ठाकरे, लखीराम अग्रवाल, डॉ. रमन सिंह, सरोज पांडे, प्रेमप्रकाश पांडे, मूलचंद खण्डेलवाल, डॉ. डी. पी. अग्रवाल, बनवारी लाल अग्रवाल जैसे नेता यही महसूस करते थे कि लोकल नेतृत्व का उभार उनकी राजनीति को खत्म कर देगा. इसलिए लोकल को मोहरा बनाकर लगातार नेतृत्व गैर छत्तीसगढ़ी हाथों में रखा गया. ऐसा नहीं है कि राज्य में छत्तीसगढ़ी नेतृत्व का अभाव था. सात बार के सांसद रमेश बैस, नंदकुमार साय, दिलीप सिंह जूदेव, बलिराम कश्यप, ताराचंद साहू, सोहन पोटाई, गंगूराम बघेल, पुन्नूलाल मोहिले, रेशम लाल जांगड़े, राम विचार नेताम, चंद्रशेखर साहू जैसे अनेक नेताओं में अच्छी संभावना होते हुए भी इन्हें न केवल दबाया गया बल्कि षडयंत्र पूर्वक इनसे सत्ता प्रमुख होने की दावेदारी छीनी गई.

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भाजपा - कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता भी हैं जो बेवजह

बाहरी होने का आरोप झेल रहे हैं जबकि हकीकत यह है कि वे यहाँ की संस्कृति और परिवेश में घुल मिल गए है. भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल का नाम इसमें प्रमुखता से लिया जा सकता है.

कांग्रेस में भी गैर छत्तीसगढ़ी नेतृत्व के उभार ने ही भाजपा को राज्य में घुसने का मौका दिया था. चंदूलाल चंद्राकर, अरविन्द नेताम जैसे नेताओं के स्थान पर शुक्ल बंधुओं और मोतीलाल वोरा को तरजीह मिलने से कांग्रेस घटती रही. इस बात को अब कांग्रेस भी मानने लगी है कि छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान को सामने रखकर राज्य की राजनीति में सिरमौर बने रहा जा सकता है.

राज्य में कांग्रेस सरकार बनाने के बाद ही राज्य शासन ने अपने ध्येय वाक्य में "बात हे अभिमान के - छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के" जोड़कर संकेत दे दिया था. राज्य मे 52% पिछड़े वर्ग और लगभग 32% आदिवासी जनता को सामने रखकर नीतियाँ निर्धारित की गई. यह तबका ज्यादातर धान की किसानी

परदेशियों को पुचकारने का ही खामियाजा है कि भाजपा सत्ता की पटरी से उतर गई, स्थानीय लोगों की तरफ हाथ बढ़ाने से आज कांग्रेस का हाथ प्रदेश में लगातार मजबूत होता जा रहा है.

से जुड़ा हुआ है इसलिए धान की बढ़ी कीमतों ने उस पर जादुई असर किया. उसके बाद वनोपज की सरकारी खरीदी, गोधन न्याय योजना के तहत गोबर की खरीदी, राम वन गमन पथ के निर्माण से आस्था की बढ़ोत्तरी, सभी उच्च पदों पर छत्तीसगढ़ी व्यक्ति को नेतृत्व आदि ने यहाँ के मूल निवासियों में यह स्थापित किया कि राज्य की राजनीति में उनकी भागीदारी सर्वोच्च होनी चाहिए. राज्य सरकार इस धारणा को और हवा दे रही है.

यही कारण है कि जिन नगरीय निकाय क्षेत्रों में कभी भाजपा बेहद मजबूत हुआ करती थी वहाँ भी वह छत्तीसगढ़वाद के उभार की वजह से पिछड़ गई. अब वह यहां नई जमीन तलाश कर रही है.

भाजपा के पास वर्तमान में भी विजय बघेल, अजय चंद्राकर, नंद कुमार साय, धरम लाल कौशिक, विष्णु देव साय, राम विचार नेताम, पुन्नुलाल मोहिले अनेक नेता मौजूद हैं लेकिन पार्टी को आज भी डॉ. रमन सिंह, राजेश मूणत, सरोज पांडे, शिव रतन शर्मा, प्रेमप्रकाश पांडे, अमर अग्रवाल, गौरी शंकर अग्रवाल जैसे नेता ही चला रहे हैं. जिनके बाहरी होने को कांग्रेस लगातार प्रचारित कर रही है और भुना भी रही है. यदि राज्य में कांग्रेस का सामना करना है तो भाजपा को स्थानीय नेतृत्व को सामने लाना होगा और छत्तीसगढ़ में जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को स्थापित करना होगा अन्यथा छत्तीसगढ़ ने शायद अब यह समझ लिया है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कैसे बना जा सकता है.

छत्तीसगढ़ गढ़ रहा

शिक्षा का नया इतिहास

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम शालाओं से छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण के क्षेत्र में एक नया इतिहास लिख रहा है. पिछले तीन वर्षों में इन स्कूलों की संख्या 171 तक जा पहुंची है. इन विद्यालयों में 72 हजार से अधिक विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. माध्यमिक कक्षा तक शिक्षण पूर्णतः निःशुल्क है जबकि उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए मामूली शुल्क निर्धारित है.

» लखन लाल

जो लोग छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार को गाय-गोबर और नरवा-गरवा-घुरवा बाड़ी की सरकार कहते हैं, उन्हें लोक शिक्षण में परिवर्तन की इस बयार को गौर से देखना चाहिए. इस प्रक्रिया की शुरुआत तब हुई जब 2016 में भिलाई नगर पालिक निगम ने एमआईसी में कुछ सरकारी स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में तब्दील करने का प्रस्ताव पारित किया. कांग्रेस के युवा नेता एवं देश के सबसे कम उम्र के देवेन्द्र यादव इस निगम के महापौर थे. 2018 में छत्तीसगढ़ विधानसभा ने इस प्रस्ताव पर स्वीकृति की

हिन्दी मीडियम शालाओं का क्या होगा

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना पर बल दिए जाने से यह सवाल उठने लगा है कि हिन्दी माध्यम की शालाओं का क्या होगा? शिक्षाविदों का मानना है कि अभी तो इनका महत्व बना रहेगा. छत्तीसगढ़ शासन के अधीन फिलहाल 54000 से अधिक विद्यालय हैं. इन स्कूलों में अनुभवी शिक्षकों की एक बड़ी टीम काम कर रही है. इनमें से अनेक स्कूल अपनी गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं. वैसे भी सफलता का ग्राफ देखें तो हिन्दी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चों का प्रदर्शन समान रहता है. भिलाई में बीएसपी द्वारा स्कूलों का उदाहरण हमारे सामने है. पहले हिन्दी मीडियम स्कूल ही अधिक थे. पर समय के साथ एक-एक कर लगभग सभी स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित कर दिया गया. हो सकता है सरकारी स्कूलों के साथ भी ऐसा ही हो, पर इसमें काफी लंबा वक्त लगने वाला है. जब तक अनुभवी शिक्षक सेवा में हैं वे अपना स्तर गिरने नहीं देंगे, ऐसी अपेक्षा की जाती है.

मुहर लगा दी.

शासन ने इस महत्वाकांक्षी योजना को गंभीरता से लिया. इन स्कूलों के भवन का उन्नयन करने के साथ ही बेहतर फर्नीचर, उन्नत प्रयोगशालाएं, उत्कृष्ट ग्रंथागार, स्मार्ट बोर्ड आदि की व्यवस्था के दरवाजे खोल दिये. साथ ही उत्कृष्ट शिक्षकों की भर्ती का अभियान छेड़ दिया. अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में अध्यापन के लिए पहली शर्त यह रखी गई कि अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी होना चाहिए. इसका असर भी जल्द ही दिखाई देने लगा. बड़ी संख्या में बच्चों ने निजी स्कूलों को छोड़कर इन विद्यालयों में प्रवेश ले लिया.

2020 में शासन ने इन स्कूलों का नया नामकरण किया. इन्हें स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का नाम दिया. स्वामी आत्मानंद का जन्म रायपुर के ही एक गांव बरबंदा में 6 अक्टूबर, 1929 को हुआ था. उनका बचपन का नाम तुलेन्द्र वर्मा था. रायपुर में विवेकानन्द आश्रम एवं नारायणपुर में विवेकानन्द विद्यापीठ एवं अस्पताल की स्थापना उन्होंने ही की थी.

पालकों ने ली राहत की सांस

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के खुलने से उन पालकों ने राहत की सांस ली है जो पेट काटकर किसी तरह बच्चे को निजी अंग्रेजी स्कूलों में भेज रहे थे. अकसर फीस नहीं पटा पाने के कारण स्कूल में बच्चे जलील होते थे और परिवार तनाव में रहता था. शिक्षा का अधिकार के तहत शहरी क्षेत्र के नामचीन स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चे हीनभावना का शिकार हो जाते थे. अब उनकी दुश्वारियों पर विराम लगने जा रहा है. अकेले दुर्ग जिले में इस समय 16 आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित हैं.

निजी स्कूलों पर सकारात्मक दबाव

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों ने निजी क्षेत्र के स्कूलों पर भी दबाव बनाया है. अब उन्हें अपनी गुणवत्ता सुधारने तथा फीस को युक्तिसंगत बनाने के लिए जी-तोड़ मेहनत करनी होगी. शासन में परिवर्तन और नवोन्मेष को लागू करने में वक्त लगता है. इसका वे लाभ ले सकते हैं. इससे प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर शिक्षा में गुणात्मक सुधार को गति मिलेगी. निजी क्षेत्र के ऐसे स्कूल, जो माल उगाही केन्द्र बने हुए हैं, उनकी शामत आ सकती है. इसका भी लाभ अच्छे निजी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों को मिलने की संभावना

है. वैसे भी विद्यार्थियों की संख्या और आत्मानंद स्कूलों में उपलब्ध सीटों की संख्या को देखते हुए उन्हें अभी अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है. दूसरे अधिकांश निजी स्कूल सीबीएसई या सीबीएसई पैटर्न के नाम पर संचालित हैं जबकि सरकारी स्कूल छत्तीसगढ़ बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं.

शिक्षकों को भी मिलेगा लाभ

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों से शिक्षकों के उत्साह में वृद्धि हुई है. निजी स्कूलों में शोषण का शिकार हो रहे उत्कृष्ट शिक्षकों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता खुला है. यहां यह स्पष्ट कर दें कि शोषण केवल वेतन का नहीं होता बल्कि शिक्षणेत्तर कार्यों में झोंके जाने से भी उनकी गरिमा नष्ट होती है, पारिवारिक जीवन तबाह होता है. शासकीय स्कूल में वे इस भयादोहन से बचे रहेंगे. निजी स्कूलों में भी उनके प्रति व्यवहार में सुधार होने की संभावना है.

जिले के निवासी होने की अनिवार्यता खत्म

शासन स्वामी आत्मानंद स्कूलों का विस्तार पूरे राज्य में विकास खण्ड स्तर तक कर चुका है. पर इसके आड़े आ रहा है अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों का अभाव. अधिकांश अंग्रेजी माध्यम स्कूल शहरी क्षेत्रों में हैं. अधिकांश लोग अपना शहर नहीं छोड़ना चाहते. इसलिए शासन ने नियम बनाया था कि अभ्यर्थी को उसी जिले का होना चाहिए जहां वह अध्यापन करने का इच्छुक है. इससे कई जिलों में शिक्षकों की कमी महसूस की गई. 14 फरवरी, 2022 को यह अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई. अब किसी भी जिले का अभ्यर्थी राज्य के किसी भी जिले के लिए आवेदन कर सकता है. इससे राज्य के कोने-कोने में अच्छे शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सकेगा. साथ ही उत्कृष्ट शिक्षण प्रवृत्ति शिक्षा राज्य के दो-चार शहरों से निकलकर पूरे राज्य में फैल सकेगी.

सीजीबीएसई और सीबीएसई

फिलहाल सभी स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकण्डरी एजुकेशन से जुड़े हैं. आवश्यकतानुसार इनमें से कुछ स्कूलों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षण बोर्ड (सीबीएसई) में परिवर्तित करने की संभावना तलाशी जा रही है. कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले सत्र से ऐसा किया जा सकता है. बहरहाल, इस दिशा में कोई ठोस फैसला अभी नहीं आया है.

पूरा हो रहा स्वतंत्रता संग्रामियों का सपना

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से लेकर संविधान की रचना करने वालों तक का यह सपना रहा है कि उच्च स्तरीय शिक्षा देश के प्रत्येक बच्चे को सुलभ होगा. पहले-पहल तो सरकारी स्कूलों ने अच्छा काम किया पर समय के साथ शिक्षा व्यापार बन गया और यह निजी हाथों में चला गया. साधन संपन्न लोगों के बच्चे निजी स्कूलों में जाते रहे और सरकारी स्कूल धीरे-धीरे मध्यान्ह भोजन केन्द्र बनकर रह गए. छत्तीसगढ़ सरकार धारा के विपरीत तैरने की कोशिश कर रही है. यह रास्ता कठिन अवश्य है पर असंभव नहीं है. विशेषकर पिछले 3-4 सालों की उसकी मेहनत जिस तरह से रंग ला रही है, उससे उम्मीदों को बल मिलता है. आने वाले वर्षों में यह कोशिश देश में लोक शिक्षण का नया अध्याय लिखेगी.

विश्व का सबसे बड़ा स्कूल

हाल ही में छात्रों की सबसे अधिक संख्या वाले सिटी मोंटेसरी स्कूल लखनऊ का नाम गिनीज़ बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकार्ड्स में शामिल किया गया है. सत्र 2019-20 में सिटी मोंटेसरी स्कूल ने अध्ययनरत सबसे अधिक विद्यार्थी का कीर्तिमान हासिल किया है. इस स्कूल में छात्र-छात्राओं की संख्या लगभग 56,000 है.

सिटी मोंटेसरी स्कूल (CMS) : यह अंग्रेजी माध्यम का निजी स्कूल है, जहां प्री-स्कूल से ग्रेड-12 तक की शिक्षा दी जाती है. यह स्कूल लखनऊ में है. यह CISCE (Council for Indian School Certificate Examinations) तथा CAIE (Cambridge Assessment International Education) से मान्यता प्राप्त है. 2014 में सिटी मोंटेसरी स्कूल सोसाइटी को संयुक्त राष्ट्र जन सूचना विभाग द्वारा NGO के रूप में मान्यता दी गयी थी. 2002 में सिटी मोंटेसरी स्कूल को 'यूनेस्को प्राइज फॉर पीस एजुकेशन' से सम्मानित किया गया. इस स्कूल को दलाई लामा द्वारा भी 'होप ऑफ़ ह्यूमैनिटी' पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

सेवा सहकारी समिति
मर्यादित बचेड़ी
जिला कबीरधाम, पंजीयन क्रमांक : 994
समस्त क्षेत्रवासियों को होली पर्व की
हार्दिक
शुभकामनाएं
संतोष कुमार गंधर्व
प्रभारी अधिकारी
हीरालाल पाली
समिति प्रबंधक

सेवा सहकारी समिति मर्यादित
सहसपुर लोहारा
जिला: कबीरधाम, पंजीयन क्रमांक: 1692
आप सभी को होली की
हार्दिक
बधाई
संचालक मंडल सदस्य
पूनमचंद चोपड़ा
अध्यक्ष
गंगादास मानिकपुरी
समिति प्रबंधक

सेवा सहकारी समिति मर्या. राम्हेपुर
(जरहाटोला), जिला: कबीरधाम, पं. क्र.: 1245
समस्त क्षेत्रवासियों को
महाशिवरात्रि एवं होली पर्व की
महादेव
हार्दिक
बधाई
बंशीराम साहू
अध्यक्ष
देवेन्द्र कुमार साहू
समिति प्रबंधक
उपाध्यक्ष
बनवालीराम साहू, श्रीमती उर्मिला साहू
सदस्यगण
श्रीमती जानकी बाई साहू, लेखनूराम साहू, गुनुराम साहू
चौकीराम पटेल, मनभारत पटेल, लाहुराम पटेल, भारतलाल वर्मा,
राम कुमार धुर्वे

आ. जा. सेवा सहकारी समिति
मर्यादित रेंगाखारकला
शाखा: सहसपुर लोहारा, जिला: कबीरधाम, पं. क्र. : 2031
महा शिवरात्रि
एवं
होली पर्व
की
हार्दिक
बधाई
प्रबुद्ध कुमार गौतम
प्रभारी अधिकारी
लोकचंद राहंगडाले
संस्था प्रबंधक

स्वामी आत्मानंद स्कूल भिलाई-3

दोहराएगा इतिहास

भिलाई-3 के जनता स्कूल का काया पलट हो रहा है. यहां के विद्यार्थियों को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में शिफ्ट कर दिया गया है. अब यह स्कूल स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में परिवर्तित हो चुका है. यहां उपलब्ध सुविधाओं से बच्चे अब लाभान्वित होंगे और आगे चलकर देश में नाम रोशन करेंगे. यह वही स्कूल है जहां कभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिक्षा ग्रहण किया था. आने वाले समय में यह स्कूल शिक्षा का रोल मॉडल बनेगा. ऐसी उम्मीद की जा रही है.

■ **प्रकाश लोहाना**
पूर्व अध्यक्ष, जनभागीदारी समिति
जनता स्कूल भिलाई-3

» श्याम लाल साहू

स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल, भिलाई-3 अपने गौरवशाली इतिहास को दोहराने की तैयारी में जुटा है. कभी यह भवन जनता उच्चतर माध्यमिक शाला का हुआ करता था जिसकी ख्याति दूर-दूर तक थी. प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री भी इसी स्कूल के छात्र रहे हैं. इस स्कूल ने कई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारी, उद्योगपति और जनप्रतिनिधि अंचल को दिए हैं. 2020 में अंग्रेजी माध्यम शाला में रूपान्तरित हुए इस स्कूल ने आरंभिक वर्षों में ही अपनी धाक जमा ली है. लोग निजी स्कूलों को छोड़कर यहां दाखिला ले रहे हैं.

छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना के तहत 2020 में दुर्ग जिले में कुल 5 स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए थे. भिलाई-3 का शासकीय जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भी इसमें शामिल था. शिक्षकों ने दोगुने उत्साह के साथ काम करना शुरू किया. नतीजा भी सामने है. अब यहां के पहली दूसरी के बच्चे भी अंग्रेजी बोलने लगे हैं.

स्कूल की प्राचार्य श्रीमती मीरा ने बताया कि स्कूल को उसका गौरवशाली अतीत लौटाने के लिए शिक्षक दोगुने उत्साह के साथ काम कर रहे हैं. स्कूल में प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक की कक्षाएं लगती हैं. नया सेटअप मिल गया है जिसमें संविदा के तहत नए भर्ती किए गए इंग्लिश मीडियम के शिक्षकों सहित प्रतिनियुक्ति पर आए शिक्षक शामिल हैं.

गुणवत्ता की कवायद

आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 40 विद्यार्थी होंगे. इनमें से कम से कम आधी सीटों पर छात्राओं की भर्ती प्राथमिकता के आधार पर होगी. स्कूल में पहली से आठवीं तक की कक्षाओं के लिए 8 शिक्षक एवं दो प्रधानपाठक है. इसी तरह उच्चतर माध्यमिक के लिए 10 शिक्षक व्याख्याता एवं एक प्राचार्य है. इसके अलावा तीन प्रयोगशाला सहायक, एक कम्प्यूटर टीचर, एक लाइब्रेरियन तथा एक पीटीआई नियुक्त किये जा चुके हैं. चतुर्थ श्रेणी के चार कर्मचारी तथा एक चौकीदार की नियुक्ति की गई है.

पालकों को बड़ी राहत

बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए लोग अपने बच्चों को महंगे निजी स्कूलों में भेजते थे. भारी भरकम फीस के अलावा इन स्कूलों में किसी न किसी बहाने उगाही लगी ही रहती है. अब जबकि उतनी ही या उससे भी अधिक गुणवत्ता की शिक्षा सरकारी स्कूल में मुफ्त में मिल रही है तो पालकों ने राहत की सांस ली है. आत्मानंद स्कूल में बच्चों का दाखिला कराने के लिए होड़ लग गई है.

सभी योजनाओं का लाभ

स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क है. सभी शिक्षक या तो उच्च शिक्षित हैं. इनमें से कई के पास टीचिंग का लंबा अनुभव है. यही नहीं बालिका शिक्षा के लिए चलाई जाने वाली सभी शासकीय योजनाओं का लाभ यहां भी मिल रहा है. इसमें छात्रवृत्ति के अलावा मुफ्त गणवेश तथा छात्राओं को सरस्वती साइकिल योजना का लाभ दिया जा रहा है. माध्यमिक तक सभी बच्चों को निःशुल्क मध्यान्ह भोजन भी दिया जा रहा है. यही कारण है कि अब शासकीय कर्मचारी और व्यापारी भी अपने बच्चों को यहां दाखिल करने के लिए उत्साहित हैं. प्राचार्य श्रीमती मीरा ने बताया कि फिलहाल स्कूल में 457 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं. नए सत्र का एडमिशन अतिशीघ्र ही प्रारंभ होने जा रहा है.

तुलेंद्र से स्वामी आत्मानंद की यात्रा

छत्तीसगढ़ में अध्यात्म, शिक्षा और सामाज सेवा का अलख जगाने वाले स्वामी आत्मानंद की अल्पायु की सामाजिक दीर्घ यात्रा संघर्षपूर्ण और प्रेरक भी है. 6 अक्टूबर 1929 को रायपुर जिले के ग्राम बरबंदा में जन्मे तुलेंद्र की विलक्षण प्रतिभा और समर्पण से प्रभावित होकर 1957 में रामकृष्ण मिशन के महाध्यक्ष स्वामी शंकरानंद ने उन्हें स्वामी ब्रह्मचर्य में दीक्षित कर तेज चैतन्य नाम दिया था. अपने नाम के अनुरुप उन्होंने ज्ञान के तेज से आश्रम को आलोकित किया. हिमालय में स्वर्गाश्रम में एक वर्ष की साधना के बाद रायपुर लौटने पर स्वामी भास्करेश्वरानंद से संस्कारित होने के बाद उन्हें नया नाम मिला स्वामी आत्मानंद. लेकिन मानवीय करुणा और शिक्षा के संस्कारों का बीजारोपण उनके अंतहकरण में बचपन से ही होने लगा था. पिता धनीराम वर्मा बरबंदा गांव के पास स्कूल में शिक्षक थे और माता भाग्यवती देवी की भी धर्मपरायण थीं. फिर आज के भौतिक सुविधाओं और नैतिक मूल्यों से परे वातावरण से विलग बालक तुलेंद्र को स्वतंत्रता संग्राम के महानायक महात्मा गांधी जैसे महामना का सानिध्य मिला, जहां से सेवा और करुणा का भाव जागा. तुलेंद्र यानी धनीराम वर्मा बापू के बुनियाद प्रशिक्षण केंद्र वर्धा आश्रम में शिक्षा अर्जन करते हुए उनके सान्निध्य में उनके स्नेहिल शिष्य बन गए. वर्धा आश्रम से कुछ वर्ष बाद रायपुर लौटने के बाद उन्होंने सेंटपाल स्कूल से प्रथम श्रेणी में हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद साइंस कालेज नागपुर से भी गणित में एमएससी किया. यहां हुई एक घटना ने उनके अध्यात्म व सेवा की दिशा को सुदृढ़ कर दिया. कालेज में शिक्षार्जन के लिए छात्रावास में जगह उपलब्ध नहीं होने पर रामकृष्ण आश्रम में रहने लगे. यहीं से उनके मन में स्वामी विवेकानंद के आदर्शों ने प्रवेश किया. आत्मानंद ने आईएएस की परीक्षा में प्रथम दस सफल छात्रों में शामिल होने के बाद भी नौकरी का विचार छोड़ परीक्षा नहीं दी और आजीवन मानव सेवा का मार्ग चुना. उन्होंने स्वामी विवेकानंद के पदचिन्हों पर चलते हुए रायपुर में विवेकानंद आश्रम की स्थापना की और रामकृष्ण आश्रम की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए यहां अध्यात्म,मानवीय सेवा और शिक्षा का अलख जगाया. आज जो विवेकानंद आश्रम की भव्यता और मानवतावादी स्वरुप है, वह स्वामी आत्मानंद की साधना का ही फल है. इतना ही उन्होंने बस्तर में वनवासियों के सम्मान और उपज का वाजिब मूल्य दिलाने अबूझमाड़ प्रकल्प की न सिर्फ स्थापना की बल्कि नारायणपुर में वनवासी सेवा केंद्र प्रारंभ कर आदिवासियों की दशा और दिशा सुधारने का भी प्रयास किया. खेती के साथ पेयजल, शिक्षा व चिकित्सा के कार्य के साथ विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय और अन्य स्कूल तथा छात्रावास निर्माण अतिपिछड़े दौर में सरकार के लिए आत्ममंथन का विषय था. इसके लिए उन्हें यूनिसेफ ने प्रोत्साहित कर आर्थिक मदद भी दी. स्वामी आत्मानंद ने नागपुर में भी सेवा संस्थान की स्थापना की, जहां के अनेक विद्यार्थी बड़े-बड़े प्रशासनिक पदों के साथ खेलों में भी राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा की ध्वजा लहरा रहे हैं. प्रदेश सरकार उनके आदर्शो के अनुरुप अनुसूचित जाति, जनजाति क्षेत्रों में समाजोत्थान पर ध्यान दे रही है. किसानों को उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के साथ वनवासियों के कल्याण के लिए भी कार्य करने का प्रयास कर रही है. शिक्षा में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की स्थापना कर सामान्य बच्चों को भी शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है. लेकिन स्वामी आत्मानंद के विवेकानंद और महात्मा गांधी के नैतिक स्वरुप से समग्र समाजोत्थान और दुव्यवर्सनमुक्त समाज के सपने को साकार करना अभी भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है.

स्वामी आत्मानंद स्वामी विवेकानंद के पदचिन्हों पर चलते हुए रायपुर में विवेकानंद आश्रम की स्थापना की और रामकृष्ण आश्रम की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए यहां अध्यात्म,मानवीय सेवा और शिक्षा का अलख जगाया.

छत्तीसगढ़ की फ्लैगशिप योजना से जुड़ेगा कृषि विश्वविद्यालय

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति डॉ गिरीश चंदेल कृषि विश्वविद्यालय को सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं से जोड़ने की कोशिश करेंगे. उन्होंने कहा है कि नरवा-गरुवा-घुरवा-बाड़ी से लेकर गोधन न्याय योजना का मकसद किसानों को लाभान्वित करना है. विवि की पूरी कोशिश होगी कि कृषि अनुसंधानों का पूरा लाभ किसानों को मिले. यही नहीं विश्वविद्यालय कृषि उपज के विपणन में भी किसानों की स्ट्रैटेजिक मदद करेगा. शासन की मिलेट मिशन भी उनकी प्राथमिकता में होगी.

गांव तक पहुंचाएंगे कृषि शोध का लाभ

-डॉ. चंदेल

» छ.ग. आजतक ब्यूरो

डॉ चंदेल पदभार ग्रहण करने के बाद छत्तीसगढ़ आजतक से चर्चा कर रहे थे. अंतरराष्ट्रीय ख्यातिलब्ध वैज्ञानिक डॉ चंदेल ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा कृषि और किसानों के जरिए गांवों को मजबूत करने की है. इसलिए प्राथमिकता के आधार पर गांव, गाय और गोठान आधारित कृषि अनुसंधान एवं तकनीकी का प्रचार प्रसार किया जाएगा.

गोबर से बने खाद-वर्मी कम्पोस्ट की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उसे ईएम टेक्नोलॉजी से जोड़ना पड़ेगा. इससे फंगस और बैक्टीरिया से बचाव होगा और खाद की गुणवत्ता में 8 से 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होगी. साथ ही इससे उत्पादित उपज के आहार से लोगों के स्वास्थ्य में अनुकूल वृद्धि होगी.

उन्होंने कहा कि आज किसानों की सबसे बड़ी समस्या कृषि उत्पादों की मानक तथा गुणवत्ता को बनाए रखना है. फसल के जैविक उपज को छोटे-छोटे पैकेजिंग से जोड़कर किसानों की आय में वृद्धि हेतु बाजार उपलब्ध कराना है. ताकि किसानों को कृषि उत्पाद का सही मूल्य मिल सके. इसमें विश्वविद्यालय प्रत्येक कदम पर किसानों के साथ खड़ा दिखेगा.

विश्वविद्यालय में नई संस्कृति लाने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि कृषि विकास एवं अनुसंधान हेतु कामधेनु विश्वविद्यालय, उद्यानिकी विश्वविद्यालय एवं राज्य के कृषि संबंधी विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा. साथ ही नई पीढ़ी को कृषि से प्रत्यक्ष जोड़ते हुए शोध को नई दिशा दी जाएगी.

डॉ. चंदेल को कृषि शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार प्रबंधन का 30 वर्षों का अनुभव

विकास का रोडमैप

1. छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली समस्त फसलों की प्रजातियों की डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एवं भारत सरकार के जीन बैंक एवं प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी में उनका पंजीयन.
2. भारत सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में बायोटेक्नोलॉजी पार्क एवं बायो इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना. प्रथम चरण में दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा एवं बस्तर जिलों में स्थापना होगी.
3. प्रत्येक जिले में एग्री-बिजनेस इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना.
4. प्रत्येक जिले में कृषि की 10-10 कंपनियां एवं उनके सुपर मार्केट की स्थापना.
5. राज्य में लगभग 500 एफपीओ की स्थापना. इनका कार्यालय संबंधित जिलों के कृषि विज्ञान केन्द्र में होगा.
6. राज्य के प्रत्येक जिले में केन्द्रीय बायोटेक्नोलॉजी विभाग के सहयोग से बायोटेक किसान हब की स्थापना.
7. इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फीलीपींस की सहायता से राज्य की परम्परागत 50 फसल प्रजातियों का जीआई टैग प्राप्त करना. निर्यात के लिए इसकी जरूरत होती है.
8. रायपुर अथवा दुर्ग में अंतरराष्ट्रीय स्तर के बायोटेक्नोलॉजी कॉलेज एवं रिसर्च स्टेशन की स्थापना.
9. किसानों को नई प्रजातियों के विकास में शामिल कर बायोटेक्नोलॉजी विधि से फसलों की नई प्रजातियों का विकास.
10. आगामी 5 वर्षों में विश्व के 5 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय से शिक्षा अनुसंधान के लिए एमओयू एवं स्टूडेंट फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम प्रारंभ करना.
11. राज्य के प्रत्येक जिले के लिए एग्रीकल्चर एक्शन प्लान.

है. विशेष रूप से सूखा और पोषण अनुसंधान के लिए अत्याधुनिक स्टेट ऑफ आर्ट बुनियादी सुविधाओं के निर्माण और पोषण प्रबंधन पर उनका खासा जोर रहा है.

डॉ चंदेल की उपलब्धियां

1. **धान की पांच बायोफोर्टिफाईड फसल प्रजातियों** - सी.जी. जिंक राइस, सी.जी. जिंक राइस -2, जिंको राइस एम.एस. (जिंक की अधिक मात्रा वाली प्रजातियों) प्रोटेजिन (प्रोटीन की अधिक मात्रा वाली प्रजाति) तथा सी.जी. मधुराज-55 (कम शर्करा वाली प्रजाति) का विकास.
2. भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से 30 करोड़ रूपये की लागत से स्थापित बायोपार्क एवं 13 करोड़ रूपये की लागत से निर्माणाधीन बायोटेक इन्क्यूबेशन सेन्टर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका.
3. भारत सरकार की सहायता से बस्तर के छह जिलों में 4.5 करोड़ रूपये लागत की बायोटेक किसान हब परियोजना के क्रियान्वयन में अहम भूमिका.

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति बनने पर मुख्यमंत्री ने दी बधाई...

4. कृषि विश्वविद्यालय के जर्मप्लाज्म बैंक में संग्रहित धान की 24 हजार प्रजातियों की डी.एन.ए. फिंगर प्रिंटिंग में महत्वपूर्ण योगदान.

गांव से कुलपति तक का सफर

देश के प्रख्यात पौध प्रजनक और जैव प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक डॉ. गिरीश चंदेल छत्तीसगढ़ के सिमगा, हथबंद के ग्राम-कुकरा चुन्दा के मूल निवासी हैं. उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान एवं विकास कार्यों का वृहद अनुभव है. उन्होंने इंटरनेशनल जेनेटिक इंजीनियरिंग एवं बॉयोटेक्नोलॉजी सेंटर में पी एच.डी. फेलो तथा इंटरनेशनल राईस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विजिटिंग वैज्ञानिक के रूप में कार्य किया है. उन्हें अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फैलोशिप एवं सम्मान भी प्राप्त हुए हैं जिनमें इंटरनेशनल राईस रिसर्च इंस्टिट्यूट मनीला, फिलिपिंस से डॉक्टोरेट फौलोशिप, एन.ई. बोरलॉग फैलोशिप, यू.एस.ए. यंग साईंटिस्ट अवार्ड, आउट स्टैंडिंग अचिव्हमेन्ट यूनिवर्सिटी अवार्ड आदि प्रमुख हैं. डॉ. चंदेल अनेक प्रतिष्ठित समितियों में सदस्य भी रहें हैं. छत्तीसगढ़ बायो प्रमोशन सोसायटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में उन्होंने अनेक परियोजनाओं को छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किया. वे भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा गठित टास्क फोर्स एवं मानव संसाधन विकास टास्क फोर्स के सदस्य हैं. डॉ. चंदेल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 50 रिसर्च पेपर एवं 3 पुस्तकों के चैप्टर का प्रकाशन भी किया गया है.

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति पद पर डॉ. गिरीश चंदेल की नियुक्ति होने से बाहरी और स्थानीय कुलपति के विवाद का पटाक्षेप हो गया है. इसी के साथ राजभवन और राज्य सरकार के बीच उभरी तल्खी खत्म हो गई है. उम्मीद है कि नए कुलपति की नियुक्ति से कृषि शोध और वैज्ञानिक प्रयोगों को बढ़ावा मिलेगा.

छत्तीसगढ़ आजतक ने स्थानीय कुलपति की नियुक्ति के मुद्दे को लेकर पिछले 6 माह से निरंतर अभियान चलाया था. वह सफल हो गया. इससे स्थानीय प्रतिभा को अवसर मिलेगा, यह उम्मीद है.

- संपादक

आत्मनिर्भर गांव का सपना साकार करेगा

सीएस वीटीयू

आज का युग तकनीक का है. ब्लैकबोर्ड और किताब के आधार पर ली जाने वाली शिक्षा से व्यक्ति का समग्र विकास संभव नहीं है, परंतु इसका आगाज दुनिया में कम्प्यूटर क्रांति के साथ ही हो चुका है. अब साक्षरता का अर्थ अक्षर ज्ञान से न होकर व्यक्ति के प्रौद्योगिक प्रणालियों के संचालन के ज्ञान से किया जाता है. जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इंटरनेट और कम्प्यूटर्स का उपयोग होने लगा है. "भर लो दुनिया मुट्ठी में" वाली कहावत आज प्रासंगिक हो गया है.

एक अभिनव योजना के तहत छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय ने तकनीकी विद्यार्थियों को सीधे गांव से जोड़ने की योजना बनाई है. इसे विस्तार देने के लिए देश भर के तकनीकी संस्थानों को एक छत के नीचे लाने का प्रयास किया जा रहा है. इसके लिए सीएसवीटीयू ने 2019 में इंडियन सोसाइटी फॉर टेक्नीकल यूनिवर्सिटीज की स्थापना की है. सीएसवीटीयू इसी सत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस में बीटेक ऑनर्स का पाठ्यक्रम भी प्रारंभ करने जा रहा है.

सीएसवीटीयू के कुलपति डॉ. एमके वर्मा ने "छत्तीसगढ आजतक" से चर्चा के दौरान उक्त जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पंचवर्षीय योजनाओं को प्रारंभ करते समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने कहा था – "भारत ग्रामों में ही बसता है, गांव भारत की आत्मा है". सीएसवीटीयू इस कथन को चरितार्थ करने का प्रयास करेगा. इसके लिए विश्वविद्यालय आगामी सत्र 2022-23 में 42 ग्रामों को गोद लेने जा रहा है. इन गांवों में योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे.

सीएसवीटीयू इसके साथ ही 50 ग्रामीण उच्च माध्यमिक शालाओं को गोद लेगा. इन शालाओं के 10वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत कम्प्यूटर के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसका उद्देश्य उनमें तकनीक के प्रति रुचि जगाना एवं तकनीक के महत्व को स्थापित करना होगा. प्रशिक्षित छात्रों की मदद से इसका विस्तार पूरे राज्य में किया जाएगा.

» छ.ग. आजतक ब्यूरो

शोध एवं विकास के लिए 42 गांवों को लिया गोद

बीटेक में ऑनर्स कोर्स प्रारंभ

वक्त के साथ कदमताल करते हुए छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स एवं डेटा साइंस में बीटेक ऑनर्स पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का फैसला लिया है. इसमें 180 सीटें उपलब्ध होंगी. इन सीटों के लिए प्रवेश जेईई तथा पीईटी के माध्यम से ही होगी. इसके साथ ही सीएसवीटीयू इस पाठ्यक्रम को उपलब्ध कराने वाले देश के चुनिंदा विश्वविद्यालयों में शामिल हो जाएगा. उल्लेखनीय है कि एआईसीटीई ने सत्र 2021-22 में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के देश भर में 40 हजार सीटों को अनुमति प्रदान की थी. इसके साथ ही डेटा साइंस की 11,040 को भी मंजूरी दी थी. इसे अच्छा प्रतिसाद मिला है.

तकनीकी के उपयोग का रोडमैप

कुलपति डॉ वर्मा का मानना है कि तकनीकी का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक रोडमैप होना चाहिए. इसके लिए ग्रामीण एवं नगरीय निकायों के साथ मिलकर काम करना होगा. राज्य शासन के 52 ऐसे विभाग हैं जो तकनीकी का किसी न किसी रूप में उपयोग करते हैं. यदि ये सभी विभाग शिक्षा एवं तकनीकी का उपयोग विभागीय कामकाज के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए करेंगे, तो बेहतर नतीजे आ सकते हैं. यदि ऐसा हुआ तो छत्तीसगढ़ बदलेगा और "छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया" पूरे देश की जुबान पर होगा. प्रतिभा का पलायन रुकेगा और राज्य शिक्षा का हब बन जाएगा.

तकनीकी समाज का रक्त

"जिस प्रकार से रक्त पूरे शरीर की निर्माणकारी एक-एक कोशिका तक भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाता है, ठीक उसी प्रकार तकनीकी समाज के लिए रक्त का काम करता है. यह समाज के एक-एक व्यक्ति को पहचान कर, उस तक उसकी आवश्यकता के अनुरूप सामग्री पहुंचाने का कार्य करता है. इस महती कार्य में शिक्षण संस्थाएं हृदय और फेफड़ों की तरह काम करें तो समाज स्वस्थ और विकसित होता रह सकता है."

कृषि में ड्रोन का उपयोग

सीएसवीटीयू मानवरहित वायुयान तकनीकी में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है. इस तकनीकी के माध्यम से तमाम सर्वेक्षण कार्यों को शुद्धतम रूप में न्यूनतम त्रुटियों के साथ किया जा सकता है. इससे समय और मानव संसाधन की भी बचत होगी. कृषि के क्षेत्र में, जहां कुशल श्रमिकों का अभाव लगातार महसूस किया जाता है, इस तकनीक का उपयोग कर फसलों की बुआई, खाद व कीटनाशकों का छिड़काव और सतत् निगरानी के लिए किया जा सकता है. इस तकनीक का उपयोग जैविक खाद के निर्माण, पैकेजिंग और मार्केटिंग में भी किया जा सकता है.

ड्रोन तकनीक की महत्ता इस बात से भी समझी जा सकती है कि दुर्गम पहाड़ियों और बर्फीले क्षेत्रों में इनके माध्यम से कोविड टीके एवं सैन्य सामग्रियों को पहुंचाने में मदद मिली है. कुछ शहरों में इस तकनीक का उपयोग डोर-2-डोर प्राडक्ट डिलीवरी के लिए भी किया जाता है. इस तकनीक का उपयोग पर्यावरण वानिकी के क्षेत्र में भी किया जा सकता है.

रोल मॉडल बनेगा छत्तीसगढ़

डॉ वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में असीम संभावनाएं हैं. यदि आज भी यह राज्य अपने औद्योगिक, कृषि और वाणिज्यिक विकास की बाट जोह रहा है तो इसका एकमात्र कारण उपलब्ध प्रतिभाओं का समुचित दोहन नहीं कर पाना है. प्राकृतिक संसाधनों के असीमित भंडारों का समुचित दोहन और उपयोग करने में अक्षमता के लिए शासन, प्रशासन एवं नीति नियंताओं की अकुशलता ही जिम्मेदार है. अन्यथा कोई कारण नहीं कि भारत के हृदय स्थल में स्थित यह राज्य अपनी उपलब्धियों से देश के शिखर पर पहुंच न सके, यह देश के विकास का रोल मॉडल बन सकता है.

विश्वविद्यालय ने एक अमेरिकी संस्था "न्यूक्लियस टेक" के साथ 200 करोड़ की एक कार्य योजना पर अनुबंध किया है, जिससे न केवल तकनीकी प्रशिक्षणों और उपकरणों की आपूर्ति होगी बल्कि 100 लोगों को रोजगार भी मिलेगा.

शानदार ट्रैक रिकार्ड

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना 2005 में भिलाई में की गई थी. तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने इसकी आधारशिला रखी थी. विश्वविद्यालय द्वारा तकनीकी शिक्षा के अलावा अनेय व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है. इसके अधीन 143 महाविद्यालय पूरे प्रदेश में संचालित किये जा रहे हैं जिनमें से 130 शासकीय हैं. यहां से निकले बच्चे बड़ी संख्या में संघ लोकसेवा आयोग, लोक सेवा आयोग में चयनित हुए हैं. इसके अलावा बड़ी संख्या में यहां से निकले छात्र विदेशों में लब्ध प्रतिष्ठ संस्थानों में प्रशासन, प्रबंधन एवं तकनीकी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं.

समान शिक्षा पर असमान गुणवत्ता

» राजेन्द्र राव

वर्तमान में शासन का 'समान शिक्षा' का रोडमैप दूर की कौड़ी साबित हो रही है. शासन प्रत्येक जिले के कई निजी स्कूलों के आरक्षित सीटों पर शैक्षणिक शुल्क के रूप में करोड़ों रुपए का भुगतान कर रही है. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए का भुगतान कर रही है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने के नाम पर करोड़ो रूपए की सामग्री की खरीदी कर स्कूलों में केवल डंप की जा रही है. आईसीटी के लैब ई क्लास रूम के नाम पर, अटल टिंकरिंग लैब, सुपोषण अभियान के नाम पर, फर्नीचर, यूनिफार्म, साइकिल, पाठ्यपुस्तक आपूर्ति के नाम पर मोटी दलाली खाई जा रही है, और अनुपयोगी आवश्यक प्रायोगिक सामग्री खेल सामग्री स्कूलों में डंप की जा रही है. सर्वे सूची के एक-एक नाम से कई लोग लाभ उठा रहे हैं. जिसकी किसी भी स्तर पर जांच नहीं होती है ऐसे में 'सबको शिक्षा सबका अधिकार' का लक्ष्य कैसे पूरा किया जा सकता है.

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में लागू किया गया. इसका मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना है. इस अधिनियम को सर्व शिक्षा अभियान तथा वर्ष 2005 के विधेयक का ही संशोधित रूप कहा जाए तो अप्रासंगिक नहीं होगा. ज्ञात हो कि किसी भी देश के विकास में शिक्षा का विशेष महत्व है. भूतकाल में संसार को प्रेम शांति का संदेश देने और ज्ञान विज्ञान का पाठ पढ़ाने वाला विश्व गुरु के नाम से विख्यात हमारा देश भारत था. आज भारत देश में शिक्षा की गुणवत्ता धीरे-धीरे कम होती जा रही है. यही कारण है कि आज बच्चे निजी स्कूलों के साथ-साथ विदेशों से शिक्षा प्राप्त करना ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं. यदि यही स्थिति लगातार बनी रही तो हमारा देश एक दिन साहित्य, संगीत, कला, अध्यात्म जैसे क्षेत्रों से भी दूर हो जाएगी. दरअसल मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से जरूरी है समान शिक्षा. अच्छा होता कि सरकार मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का बिल लाने पर जोर देने के बजाय कॉमन स्कूल का बिल लाने पर ध्यान केंद्रित करती. सवाल यह है कि सरकार यह घोषणा क्यों नहीं करती कि देश का हर बच्चा एक ही तरह की स्कूल में जाएगा और पूरे देश में एक ही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा.

जाने शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है ?

यह संविधान की धारा 86 व संविधान संशोधन की धारा 21 ए विधेयक है यह 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ. यह 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के गरीब और बेसहारा बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है. यह संवैधानिक प्रावधान धारा 13, 15 (1,3) 17, 25 (1) 28 (1,2,3), 29 (1,2) 30, 45, 239 और 350 बी तथा केंद्रीय सूची में 63 वीं और 66 वीं अनुसूची में सभी को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है.

क्या है अधिनियम की विशेषताएं ?

यह संवैधानिक प्रावधानों को अधिकार के रूप में लोकार्पण किया गया है. इसके पालन को अनिवार्य बनाकर उल्लंघन को दंडात्मक स्वरूप दिया गया. बस्ते का बोझ और परीक्षा के भय को खत्म किया गया. पांचवीं और आठवीं की ज़िला स्तरीय और संभाग स्तरीय बोर्ड को खत्म करके स्थापना संबंधी व्यय भार को कम किया गया है. इनके माध्यम से पनप रहे भ्रष्टाचार को खत्म करने का प्रयास हुआ है. नामी-गिरामी निजी विद्यालय में बच्चों को प्रवेश के सपने को साकार किया गया है.

क्या है खामियां विधेयक की ?

प्रवेश के प्रावधान तय करने की जिम्मेदारी राज्यों को सौंप दी गई. आवश्यक राशि व संसाधनों को उपलब्ध कराने में सरकारें विफल रही हैं. केवल 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को इसके दायरे में रखा गया है. परीक्षाओं का उचित विकल्प ना होने और फेल ना होने के भय से बच्चों में पढ़ने और शिक्षकों में पढ़ाने की प्रवृतियां कम हो गई. इसका परिणाम यह हुआ कि अब आठवीं पास बच्चों को अपना नाम लिखना और अपनी पुस्तकों को पढ़ना तक नहीं आता. निजी शालाओं की संख्या निरंतर बढ़ती गई और सरकारी शालाओं की प्राथमिक कक्षाओं में दर्ज संख्या लगातार घटती जा रही है. सरकार द्वारा निजी शालाओं को गरीब और बेसहारा बच्चों को पढ़ाने के लिए दी जा रही आर्थिक मदद प्राथमिक स्तर पर प्रति छात्र 5000 रुपए और पूर्व माध्यमिक स्तर पर प्रति छात्र 7500 रुपए देय होने के कारण वे लगातार मजबूत हो रहे हैं और इसके विपरीत शासकीय शालाएं बंद होने के कगार पर पहुंच गई है. तय मानकों का पालन, छात्र व शिक्षक का अनुपात, संसाधनों की उपलब्धता, निगरानी एवं नियामक संस्थाओं का गठन करने में यह राज्य फिसड्डी साबित हो रहा है. स्थिति यह है कि प्रवेश के अनुचित प्रावधानों के कारण वास्तविक गरीब और बेसहारा वर्ग के बच्चे आज भी प्रवेश से वंचित है.

वर्ष 2002 और 2011 की सर्वे सूची में पालक के नाम शामिल रहने की अनिवार्यता इसमें नए प्रकार के भ्रष्टाचार को जन्म दिया है. गरीब परिवार के जिन बच्चों को शाला प्रवेश नहीं मिला है. वे अपने आपको इस वातावरण में समायोजित नहीं कर पा रहे हैं और सत्र के बीच में ही शाला त्यागी हो रहे हैं. इनकी मॉनिटरिंग की कोई उचित व्यवस्था नहीं है. ज्यादातर अपात्र लोग फर्जी दस्तावेजों के सहारे इस योजना का अनुचित लाभ ले रहे हैं. दिल्ली सरकार ने समुचित कार्यवाही कर इस अनियमितता को उजागर किया है. पर छत्तीसगढ़ में न तो बाल संरक्षण आयोग और न ही फीस नियामक आयोग और न ही राज्य व जिला समितियां गठित हुई, और न ही कोई सार्थक कार्य हुए हैं.

विसंगतियां क्या है ?

गरीब और बेसहारा परिवार की पहचान हेतु ग्रामीण क्षेत्र में 2002 और शहरी क्षेत्र में 2011 के बीपीएल सर्वे सूची में नाम होने की अनिवार्यता, स्कूटनी का कोई तंत्र नहीं हैं. अपात्र लोग फर्जी दस्तावेजों के सहारे शाला प्रवेश ले रहे हैं. प्रवेश छात्र सतत अध्ययन कर रहे हैं या नहीं इसकी जांच का कोई तंत्र नहीं है. इससे साला त्याग रहे छात्रों का कोई लेखा-जोखा नहीं है. प्रवेश के लिए पात्र अनेक लोगों के आवेदन दस्तावेजों में कमी के आधार पर निरस्त कर रहे हैं. वर्तमान में वास्तविक गरीब और बेसहारा परिवार को इस स्थल परीक्षण या प्रमाणीकरण का कोई तंत्र नहीं होने के कारण इस अधिनियम की मूल अवधारणा का पालन नहीं हो रहा है. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया लागू कर प्रशासन पारदर्शिता के नाम पर अपनी पीठ थपथपा रहा है. जबकि वास्तविक पात्र परिवार के लिए ऑनलाइन आवेदन ही अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है.

पलायनवादी और मजदूरी से जीवनयापन करने वाले पालकों के पास कौन से दस्तावेज होंगे और वे आवेदन की औपचारिकता कैसे पूरी कर सकेंगे? विचारणीय है. ऑनलाइन दिए जा रहे प्रमाण पत्रों की वैधानिकता संदेहास्पद है, कारण एक बच्चे का एक से ज्यादा प्रमाण पत्र बन जाता है.

सुगमित बनाने सुझाव

शासन को प्रत्येक नोडल केंद्रों के अंतर्गत एक समिति का गठन कर उस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पात्रों को सूचीबद्ध करना चाहिए. साथ ही दावा आपत्ति के लिए समय निर्धारित हो. पात्रों के आवेदन को ऑनलाइन जमा करने व आवश्यक दस्तावेज तैयार करने की जिम्मेदारी नोडल केन्द्रों को दी जाए. शासन निजी स्कूलों को निर्धारित फीश की राशि का भुगतान करती है. उसके बावजूद निजी स्कूल अन्य सुविधाओं के नाम पर छात्रों के पालकों से राशि की वसूली करते हैं, उन पर तत्काल रोक लगानी चाहिए.

शिक्षा के नाम पर निजी स्कूलों को दी जा रही आर्थिक सहयोग की राशि का उपयोग यदि सरकार प्रत्येक 10 हजार की आबादी में स्थित एक शासकीय प्राथमिक शाला को एवं प्रत्येक 30 हजार की आबादी में स्थित एक शासकीय माध्यमिक शाला को तथा प्रत्येक 50 हजार की आबादी में स्थित एक शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला को अंग्रेजी माध्यम की शाला में परिवर्तित करें तो उतनी ही राशि में इन शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है.

उच्च शिक्षा पर छाया कुहासा

होनहार विद्यार्थी फिर भी नहीं चाहते राज्य में पढ़ना

ढाई करोड़ की आबादी पर 800 से अधिक उच्च शिक्षा केन्द्र

बजट का पांचवा हिस्सा शिक्षा पर खर्च कर रही सरकार

छत्तीसगढ़ शासन ने शिक्षा को अपनी प्राथमिकता में रखा है. 2020-21 के बजट का लगभग 20 फीसद हिस्सा शिक्षा के लिए रखा गया था. चोटी के तमाम संस्थानों का आगमन छत्तीसगढ़ में हो चुका है. बावजूद इसके प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का राज्य से पलायन जारी है. कोरोना काल में जब विद्यार्थियों के बाहर जाने पर पूरी तरह विराम लग गया था, उस समय भी हम उनमें कोई खास उम्मीद नहीं जगा पाए. राज्य में शिक्षण संस्थानों की संख्या में बेशुमार इजाफा तो हुआ पर गुणवत्ता में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हो पाया.

» राहुल गौतम

उम्मीद जगाता उच्च शिक्षा ढांचा

एम्स, आईआईटी, ट्रिपल-आईटी, आईआईएम, आईएचएम, जैसी चोटी की संस्थाओं का छत्तीसगढ़ आगमन हो चुका है. छत्तीसगढ़ में एक केन्द्रीय, 14 शासकीय एवं 11 निजी विश्वविद्यालय हैं. इनमें संगीत विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, विधि विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय, पत्रकारिता विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय, चिकित्सा विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय शामिल हैं. विज्ञान, वाणिज्य, कला, आदि विषयों के लिए पांच विश्वविद्यालय अलग से हैं. राज्य में 26 कृषि महाविद्यालय, 7 शासकीय समेत 10 चिकित्सा महाविद्यालय तथा 64 अभियांत्रिकी महाविद्यालय शामिल हैं.

शासन ने झोंकी ताकत

छत्तीसगढ़ देश का 17वां सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है जबकि क्षेत्रफल के लिहाज से इसका स्थान 9वां है. सन 2003-04 में राज्य में जहां 116 शासकीय महाविद्यालय थे वहीं 2019-20 तक आते आते इनकी संख्या बढ़कर 253 हो गई है. अनुसूचित क्षेत्र में शासकीय महाविद्यालयों की संख्या भी इस अवधि में 40 से बढ़कर 114 हो गई है. इसमें यदि निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों को जोड़ लिया जाए तो यह संख्या 814 हो जाती है. 2020-21 के बजट में राज्य ने अपने संसाधनों का 19.7 फीसद शिक्षा को दिया था. स्कूली शिक्षा के लिए 5144 करोड़, उच्च शिक्षा के लिए 779 करोड़ तथा समग्र शिक्षा अभियान के लिए 1590 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था. राज्य की साक्षरता दर 70.28 फीसद है.

वजह तलाश रहे शिक्षाविद

वरिष्ठ शिक्षाविदों का मानना है कि उच्च शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के पर्याप्त प्रयास नहीं किये गये. पाठ्यक्रम में गुणात्मक सुधार नहीं किया गया. इंडस्ट्री इंटरफेस, साफ्ट स्किल ट्रेनिंग, हैण्ड्स ऑन एक्सपीरियंस जैसे बातें सेमीनारों तक सीमित रह गईं. लिहाजा वाणिज्य जैसे विषय की पढ़ाई के लिए भी होनहारों की पहली पसंद इंदौर, पूणे, दिल्ली जैसे शहर हैं.

शिथिलता का एक और कारण यह है कि अधिकांश विश्वविद्यालय एक दूसरे का अनुसरण कर रहे हैं. अकादमिक काउंसिल की उपस्थिति महसूस नहीं होती. ऐसा लगता है कि विश्वविद्यालय बाजारू गाइड और अनसाल्वड पेपर छापने वालों के निर्देशन में काम कर रहे हैं. अधिकांश सैद्धांतिक विषयों में विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में भी पिछले 25-30 सालों से वही-वही सवाल घुमा-फिराकर पूछे जा रहे हैं. सबकुछ ढर्रे पर चल रहा है. न पेपर सेट करने वाले को दिक्कत और न जांचने वाले को. इतनी सी पढ़ाई करने के लिए विद्यार्थियों को कालेज आना भी जरूरी नहीं लगता. अंकसूची में नियमित और स्वाध्यायी का उल्लेख न हो तो वे कालेज में दाखिला भी न लें.

एक और कारण है शिक्षा का व्यावसायीकरण. उच्च शिक्षा विभाग सहित तमाम विश्वविद्यालय ऐसे महाविद्यालयों को रोकने में असफल रहे हैं जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए बाजार में हैं. कागजी खानापूर्ति की बदौलत मान्यता प्राप्त ये महाविद्यालय बुनियादी शर्तों को भी पूरा नहीं करते. ये मामूली शुल्क पर बच्चों को प्रवेश और अटेंडेंस देते हैं. इनकी मौजूदगी का प्रतिकूल असर उन महाविद्यालयों की सेहत पर पड़ता

है जो अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं. राज्य के इंजीनियरिंग कालेज इसका सबसे अच्छा उदाहरण हैं. इनमें से कई अब बंद हो चुके हैं, पर जाने से पहले ये अभियांत्रिकी शिक्षा का माहौल खराब कर गए हैं.

कोविड काल ने दिया था मौका

कोविड काल में राज्य के उच्च शिक्षा विभाग को एक बड़ा मौका मिला था. राज्य से विद्यार्थियों के बाहर जाने पर विराम लग गया था. कालेजों में भी थोक में बच्चे पास हुए थे जिसके कारण डिग्री कोर्स के तीनों वर्ष में पर्याप्त बच्चे थे. पर उच्च शिक्षा विभाग या विश्वविद्यालय परीक्षा का प्रारूप ही तय नहीं कर पाये.

उल्लेखनीय है कि परीक्षा के स्वरूप के अनुरूप ही विद्यार्थियों को तैयार किया जाता है. चूंकि परीक्षा का स्वरूप तय नहीं किया जा सका इसलिए ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर ऑफलाइन शिक्षण को ही ढोया जाता रहा. अंत में किसी तरह परीक्षा कार्य का संपादन किया गया जिससे कोई भी खुश नहीं है.

भ्रामक है कैम्पस प्लेसमेंट ड्राइव

पहले जो कंपनियां केवल इंजीनियरिंग कालेजों में कैम्पस ड्राइव चलाती थीं अब उन्होंने डिग्री कालेजों का रुख कर लिया है. उन्हें सिर्फ ऐसे बच्चों की तलाश होती है जिनमें तेजी से सीखने की क्षमता है, जो टिककर काम कर सकें. अभ्यर्थी चाहे किसी भी कोर्स का हो, काम करने की ट्रेनिंग उन्हें प्लेसमेंट के बाद देनी ही पड़ती है. टीयर-2 शहरों के विद्यार्थी कम पैकेज में तैयार हो जाते हैं जबकि महानगरों और टीयर-1 शहरों के बच्चों की अपेक्षा बड़ी होती है.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रावधान

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में कौशल शिक्षा पर खास ध्यान दिया गया है. यूजीसी द्वारा राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अर्हता ढांचा (एनएचईक्यूएफ) के मसौदे में उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों को कौशल व व्यावसायिक शिक्षा के साथ जोड़ दिया गया है. यह उसी पाठ्यक्रम या क्षेत्र से संबंधित होगा, जिसमें छात्र-छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं. खास बात है कि इनमें डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट जैसे सभी स्तर के पाठ्यक्रम शामिल है. नए शैक्षणिक सत्र यानी वर्ष 2022-23 से इनके लागू हो जाने की उम्मीद है.

टूटी बांह पर बैगा ने बांध दी खपच्ची
एम्प्यूट करना पड़ा

एक छोटी से लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, इसका ताजा नमूना सामने आया है. 15 साल की यामिनी की बांह जख्मी हो गई थी. एक्स-रे में पता चला कि हड्डी टूट गई है जिसे ठीक करने के लिए आपरेशन कर रॉड डालना होगा. किसी ने बैगा के बारे में बताया जो ऊपर से खपच्ची बांध कर टूटी हड्डी जोड़ देता है. खपच्ची बंधी और पूरी बांह सड़ गई. मरीज की जान बचाने के लिए उसकी बांह काटनी पड़ी.

घटना बिल्हा की है. सेंट यूजीन इंग्लिश मीडियम स्कूल की 10वीं की छात्रा यामिनी 2 फरवरी को घर पर ही गिर पड़ी थी. बांह में चोट लगने पर उसे पास के ही लालचंदानी हॉस्पिटल ले जाया गया. एक्स-रे करने पर पता चला कि बांह की हड्डी टूट गई है. सर्जरी कर रॉड डालने की सलाह दी गई. किसी ने कहा कि लड़की का मामला है. सर्जरी का निशान पड़ जाएगा. एक बैगा हैं जो ऊपर से ही जड़ी बूटी का लेप लगाकर खपच्ची बांध देते हैं और हड्डी जुड़ जाती है. घर वाले उसे लेकर बैगा के पास पहुंचे. बैगा ने खपच्ची बांध दी.

दो दिन बाद बांह में भयंकर सूजन आ गया और त्वचा काली पड़ गई. उसपर फफोले निकल आए. यामिनी का एक रिश्ते का भाई पाटन में डाक्टर है. जानकारी मिलने पर उसने तत्काल यामिनी को भिलाई बुलवाया. उसे हाइटेक सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ दीपक कुमार सिन्हा के पास भेज दिया. रक्तसंचार में अवरोध के कारण बांह के नीचे का हाथ मृतप्राय हो चुका था.

डॉ दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि सूजन के कारण रक्तसंचार पूरी तरह बंद हो चुका था. रक्तसंचार रुकने के बाद मांसपेशियां अधिकतम 12-24 घंटे तक जीवित रह सकती हैं. इस केस में जख्म को सात दिन से ज्यादा बीत चुके थे. हाथ के बचने की बहुत कम उम्मीद थी फिर भी एक आखिरी कोशिश की गई. प्लास्टिक सर्जन डॉ दीपक कोठारी के साथ मिलकर 10 फरवरी को ऑपरेशन कर प्रेशर को रिलीज करने की कोशिश की गई.

डॉ. दीपक कोठारी ने बताया कि इसे कम्पार्टमेन्ट सिंड्रोम कहते हैं. सूजन के कारण नसों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है और रक्तसंचार रुक जाता है. घायल बांह को ऊपर से कसकर बांध देने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई थी. कई दिनों तक रक्तसंचार रुका रहने की वजह से बांह निष्प्राण हो चुकी थी. तमाम कोशिशें बेकार गईं और अंततः हमें कठोर निर्णय लेना पड़ा. 21 फरवरी को रोगी का जीवन बचाने के लिए उसकी बांह को एम्प्यूट (काटना) करना पड़ा. यामिनी का हौसला बरकरार है. वह जीव विज्ञान विषय लेकर आगे की पढ़ाई करने की इच्छा रखती है. पर हादसे के बाद उसकी यह इच्छा और मजबूत हुई है. जिस स्कूल में अभी वह पढ़ रही है वहां कक्षा दसवीं तक की ही पढ़ाई होती है. आगे की पढ़ाई के लिए उसे स्कूल बदलना होगा. अब वह किसी अच्छे स्कूल में दाखिला लेना चाहती है, ताकि उसके सपने पूरे हो सकें.

बस्तर के भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश नहीं भर पाई पुरंदेश्वरी

भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री डी. पुरंदेश्वरी का बस्तर दौरा इस बार पहले जैसा सनसनीखेज नहीं रहा. दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी दर्शन के बाद उन्होंने उत्तर बस्तर कांकेर और कोंडागांव का दौरा कर भले ही कार्यकर्ताओं को चार्ज किया, लेकिन संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में उनका दौरा उल्लेखनीय नहीं रहा. जगदलपुर के संजय गांधी वार्ड की कांग्रेस पार्षद के मामले का हवाला देकर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में वसूलीबाजी का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस को घेरने की कोशिश की. यह बात सही भी है कि भाजपा के दबाव के चलते ही कथित कांग्रेस पार्षद की गिरफ्तारी शनिवार को हो गई है. किंतु इन सबसे हटकर मध्य बस्तर जगदलपुर के भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं को उनका मार्गदर्शन नहीं मिल सका. वह बस्तर दौरा बीच में ही छोड़कर यूपी चुनाव प्रचार के लिए रवाना हो गई. इधर मध्य बस्तर में भाजपाई उनका इंतजार करते रह गए. पुरंदेश्वरी के अचानक चले जाने की वजह से रायपुर में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक भी रद्द कर दी गई. चुनावी दौरे में राजनीतिक दलों के तमाम बड़े नेताओं को चुनावी राज्य में प्रचार के लिए भेजा जाता है. पुरंदेश्वरी भाजपा की राष्ट्रीय ओहदेदार और तेजतर्रार नेता हैं, लेकिन वह जब छत्तीसगढ़ प्रभारी की हैसियत से राज्य के पूर्व निर्धारित संगठन दौरे पर थीं तो उनका पूरा दौरा होने के लिए एक रोज का इंतजार भी किया जा सकता था. उनके द्वारा बस्तर दौरा छोड़कर जाने पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया चाहे जो भी है. वह अपनी जगह है किंतु भाजपा को इससे निराशा ही हाथ लगी है. जगदलपुर में प्रधानमंत्री आवास मामले में भाजपा ने काफी हंगामा मचाया था. पूर्व मंत्री केदार कश्यप सहित कई नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हुई थी. राजधानी तक भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला चल पड़ा था. जगदलपुर भाजपा की उम्मीद थी की पुरंदेश्वरी आएंगी और पिछली बार की तरह प्रदेश की कांग्रेस सरकार को थूक के बहाने बहाने वाला जोश कार्यकर्ता में भरेगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. मध्य बस्तर के भाजपा कार्यकर्ता महसूस कर रहे हैं कि उनका बस्तर दौरा महज औपचारिकता ही रहा. वैसे भाजपा के भरोसेमंद सूत्र बता रहे हैं कि डी पुरंदेश्वरी अगले महीने की शुरुआत में फिर बस्तर आएंगी और मोर्चा संभालेंगी.

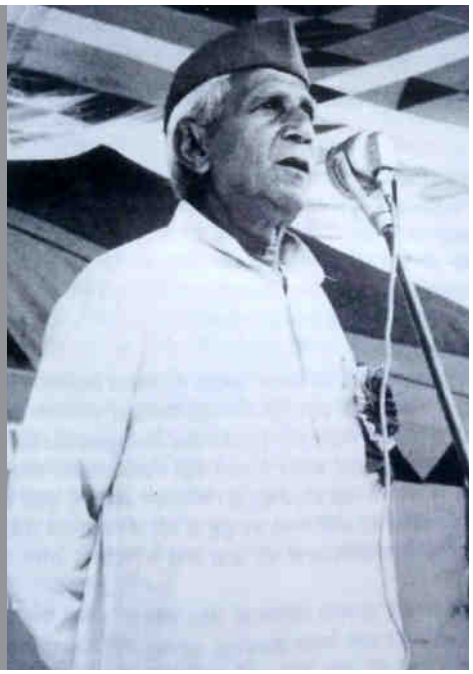

53 वीं पुण्यतिथि

मालगाड़ी से लाया गया था सांसद का शव

डॉ. खूबचंद बघेल की वजह से देश के जनप्रतिनिधियों को मिल रहा मरणोंपरांत सम्मान

डॉ खूबचंद बघेल को छत्तीसगढ़ राज्य की परिकल्पना करने वाला पहला छत्तीसगढ़िया माना जाता है. उन्होंने भातृसंघ बनाकर छत्तीसगढ़ में सबसे पहले आंदोलन खड़ा किया था. वे कहते थे जो व्यक्ति छत्तीसगढ़ का भला चाहता है, वह छत्तीसगढ़िया हैं. चाहे वे किसी जाति- धर्म या पंथ के हों. डॉ खूबचंद बघेल की उपरोक्त तस्वीर उनके निधन के ठीक 7 दिन पहले 16 फरवरी 1969 की है. जब वे अहिवारा में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य हेतु गठित भातृसंघ को संबोधित कर रहे थे. यह तस्वीर छत्तीसगढ़ की पहली सांस्कृतिक संस्था चंदैनी गोंदा के प्रथम उद्घोषक व "चंदैनी गोंदा छत्तीसगढ़ की एक सांस्कृतिक यात्रा" नामक अमूल्य कृति लिखने वाले डॉ. सुरेश देशमुख (धमतरी) ने उपलब्ध कराई है.

» हेमंत कश्यप

कृषक परिवार में जन्म लेने वाले डा. खूबचंद बघेल शासकीय सेवा छोड़ कर स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने वाले अद्भुत और अग्रणी सेनानी थे. वे अखिल भारतीय कूर्मि क्षत्रिय समाज का दो बार अध्यक्ष रहे. छत्तीसगढ़ का शोषण, यहाँ के लोगों का अपमान एवं अत्याचार से आहत होकर उन्होंने छत्तीसगढ़ भ्रातृसंघ की स्थापना की थी. पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के स्वप्नद्दष्टा डा. खूबचन्द बघेल बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे. समाज सेवा के अलावा सहकारिता, शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में भी उनका योगदान रहा है. 22 फरवरी 1969 को दिल्ली में आयोजित संसद सत्र के दौरान हृदयाघात से उनका निधन हो गया था. दिल्ली की तत्कालीन संसदीय कार्यसमिति ने उनके पार्थिव शरीर को मालगाड़ी से रायपुर भिजवा दिया था. इस अपमानजनक घटना के चलते ही पूरा छत्तीसगढ़ आंदोलित हो उठा. फलस्वरूप केन्द्र सरकार ने बाध्य होकर यह प्रस्ताव पारित किया कि "सत्र के दौरान किसी सांसद का निधन होता है तो उनके पार्थिव शरीर को ससम्मान हवाई जहाज से अथवा रेल के प्रथम श्रेणी के बोगी से भेजा जाए". तब से दिल्ली हो या किसी भी राज्य की राजधानी में किसी जनप्रतिनिधि की आकस्मिक मौत पर उनके पार्थिव देह को ससम्मान उनके घर तक शासन द्वारा पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है.

समाज को नहीं छोड़ा..

डॉ खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ की संस्कृति की यात्रा प्रारंभ करने वाले जाने-माने रंगकर्मी दाऊ रामचंद्र देशमुख के ससुर थे. मनवा कुर्मी समाज का सदस्य होते हुए देशमुख फिरका में बेटी का विवाह करने की वजह से उन्हें मनवा कुर्मी समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था. इसके बावजूद वे अपने गांव पथरी में किसी भी स्वजातीय के घर सुख-दुख का कार्य होता, वे जरूर पहुंचते थे. वहां संबंधित परिजनों से सुख- दुख की बात करने का प्रयास करते. एक कोने में चुपचाप भोजन करते और स्वयं झूठा पत्तल उठाते थे. उनके चाहने वाले उन्हें यह कहकर समझाते थे कि - डॉक्टर साहब, समाज ने आपको बहिष्कृत कर दिया है फिर भी आप सामाजिक कार्यों में आते हैं. अपमानित महसूस नहीं करते? इस पर वे हंसकर जवाब देते थे कि "भाई समाज ने मुझे छोड़ा है, मैंने समाज को नहीं छोड़ा". अंततः कुर्मी समाज ने फिरका परस्ती को छोड़ा और छत्तीसगढ़ के सभी कुर्मी एक मंच पर आ गए. सहनशीलता की मूर्ति थे डॉ. खूबचन्द बघेल.

वर्ष 1956 में जब मध्यप्रदेश राज्य बना, तब कांग्रेस हाईकमान ने डॉ खूबचंद बघेल को मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री बनाने पत्र जारी कर दिया था परंतु उन दिनों के कुछ महत्वाकांक्षी नेताओं ने दुष्प्रचार कर डॉ खूबचंद बघेल को खिन्न कर दिया, इसलिए उन्होंने स्वार्थ परक राजनीति से अलग होकर पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भातृसंघ का गठन कर छत्तीसगढ़ प्रेमियों को एक करने में जुट गए. आज छत्तीसगढ़ एक स्वाभिमानी और समृद्ध राज्य है.

श्री भूपेश बघेल जी
मान. मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री रविन्द्र चौबे जी
कृषि व जल संसाधन मंत्री, छ.ग. शासन

वर्षों से बंद पड़ी उद्वहन सिंचाई योजना फिर से प्रारंभ

1538 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसल हेतु सिंचाई सुविधा प्रस्तावित

बीते वर्षों से बंद पड़ी शासन की महत्वकांक्षी उद्वहन सिंचाई योजना कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने फिर से प्रारंभ की जा रही है.

इसी के तहत दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड की भाठागांव उद्वहन सिंचाई योजना फिर से प्रारंभ की जा रही है. जिसके तहत विशेष सुधार एवं विद्युत यांत्रिकी उपकरणों का नवीनीकरण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है. जिसमें 1538 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसल हेतु सिंचाई सुविधा प्रस्तावित हैं. इस योजना में विद्युत सबस्टेशन 750 के.व्ही.ए. 33\0.433 के.व्ही. ट्रांसफार्मर सहित काम्पेक्ट सबस्टेशन का निर्माण कार्य विभाग द्वारा किया गया है. इसमें 125 एच.पी.के 5 नग इंडक्शन मोटर और वार्टिकल टरबाईन पंप विविध उपकरणों सहित स्थापित किया गया है. इस योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है.

इसी प्रकार दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड की कौही उद्वहन सिंचाई योजना के विद्युत यांत्रिकी आधुनिकीकरण कार्य एवं नहरों का जीर्णोद्धार कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है. जिसमें 500 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई प्रस्तावित है. इस योजना में 400 के.व्ही.ए.\33\0415 के.व्ही ट्रांसफार्मर एवं 150 एच.पी के 3 नग VHS मोटर व वर्टिकल टरबाईन पंप कार्य प्रस्तावित हैं. वर्तमान में इस योजना का कार्य प्रगति पर है. जिसके पूर्णता के बाद किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान की जाएगी.

कार्यपालन अभियंता
विद्युत यांत्रिकी लाइट मशीनरी एवं नलकूप गेट संभाग दुर्ग (छत्तीसगढ़)

किसानों को मालामाल कर सकती है

रसभरी

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने रसभरी की एक ऐसी किस्म को विकसित कर लिया है जिसे कहीं भी उगाया जा सकता है. चमत्कारी औषधीय गुणों से परिपूर्ण रसभरी की इस प्रजाति को पहाड़ों पर, पठारों में तथा समतल में आसानी से उगाया जा सकता है. इसे नाम दिया गया है सीजी केपगूजबेरी.

कैपगूजबेरी (रसभरी) एक अनूठा, खट्टा-मीठा एवं रसीला स्वादिष्ट लोकप्रिय फल है तथा रुचिकर एवं स्वास्थ्यवर्धक होने के साथ ही साथ मौसमी फलों में यह अपनी विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात हैं. इसका सेवन सलाद एवं साबुत रुप में भी किया जाता है. इसमें औषधीय गुण भी विद्यमान है तथा यह फल विटामिन 'ए' तथा 'सी' का उत्तम स्रोत है. इसमें 40% प्रोटीन, 15% कैल्शियम तथा 10% विटामिन 'सी' तत्व प्राप्त होते हैं. लघुस्तरीय उद्योग स्तर पर इसका जैम तथा सॉस बनाकर धनोपार्जन किया जा सकता है.

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के फल विज्ञान विभाग द्वारा कैपगूजबेरी (रसभरी) के स्ट्रेन आईजीसीजी (सेलेक्सन-3) को सीजी कैपगूजबेरी-1 किस्म के रूप में विकसित किया गया है. इस किस्म को विकसित करने में डॉ. जी.डी. साहू, डॉ. प्रभाकर सिंह, डॉ. पूर्णेन्द्र कुमार साहू, डॉ. सरिता साहू, श्री विकास रामटेके एवं डॉ. विजय कुमार, फल विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों का योगदान रहा. इस किस्म का चयन जिला-सूरजपुर (छ.ग.) से एकत्रित कैपगूसबेरी के स्थानीय जीनोटाइप में से किया गया है. चयन के प्रथम वर्ष के दौरान कैपगूसबेरी के विभिन्न 12 जीनोटाइप के फलों को छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से बीज संग्रह के लिए चुना गया. तत्पश्चात गुणन और आगे के अध्ययन के लिए बीज बोए गए. प्रथम वर्ष के परिणामों का अवलोकन और विश्लेषण किया गया. दर्शन की जांच एवं गुणन की तैयारी की गई. फसल तुड़ाई और दो साल के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है एवं छत्तीसगढ़ के तीनों जलवायु क्षेत्रों (उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र और बस्तर के पठार) में बहुस्थानी परीक्षण किया गया है. परीक्षण में पाया गया कि कैपगूजबेरी (रसभरी) का स्ट्रेन आईजीसीजी (सेलेक्सन-3) का प्रदर्शन अन्य जीनोटाइप की अपेक्षा बहुत अच्छा पाया गया. किस्मों की विशेषताओं और उपज के प्रदर्शन के विशेष संदर्भ में किस्म सीजी कैपगूजबेरी-1 का विवरणः- **फूल आने के दिनः** 60 दिनों में जल्दी फूलना, **प्रति पौधा उपजः** 4.81 किग्रा/पौधा **विपणन योग्य उपजः** 8.11 टन/हेक्टेयर, उच्च कुल घुलनशील ठोस (टी.एस.एस. 14.20°ब्रिक्स), अच्छा स्वाद और कम बीज, सामान्य भंडारण के तहत बहुत अच्छा, उपयोगिता काल (9 दिन), परिपक्वता कालः 120-130 दिन, प्रति पौध फलों की संख्याः 96-98, प्रति पौध फलों का वजनः 12.13 ग्राम एवं इस स्ट्रेन में मुख रोग और कीट (जैसेः पत्ती धब्बे रोग, जड़ गलन, मोजैक, लाल रंग के कीट, घुन और अन्य) के प्रति सहनशीलता पाई गई. यह किस्म किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी. इस फसल एवं किस्म की खेती के लिए आवश्यक उन्नत काश्त का विवरण नीचे दिया जा रहा है

खेती के लिए भूमि का चयनः रसभरी की फसल के लिए लगभग सभी प्रकार की भूमि उपयुक्त है तथापि बलुई दोमट मिट्टी में इसकी पैदावार अधिक एवं अच्छी होती है. साधारणतः इसकी उन्नत खेती के लिए पी0एच0 6.5 तथा 7.5 क्षमता वाली भूमि अत्याधिक उपयुक्त एवं अनुकूल होती है.

रसभरी की पौध तैयार करने का समय एवं जलवायुः सर्वप्रथम रसभरी की पौध तैयार की जाती है, जिसके लिए 20 जून से 5 जुलाई तक का समय उपयुक्त माना जाता है. रसभरी की खेती के लिए औसतन 20 डिग्री सैल्सियस से 25 डिग्री सैल्सियस तापमान

अपेक्षित होता है परन्तु 15 डिग्री सैल्सियस से 20 डिगी सैल्सियस तापक्रम में भी सफलतापूर्वक इसकी खेती की जा सकती है.

बीज की मात्रा: एक हैक्टेयर कृषि क्षेत्र के लिए 200 से 250 ग्राम तक बीज की मात्रा पर्याप्त होती है.

पौधशाला में रसभरी की पौध तैयार करना: सर्वप्रथम पौधशाला के लिए निर्धारित भूभाग पर रसभरी के बीज बो दिये जाते हैं और जब वे अंकुरित हो कर अपेक्षित लम्बाई के पौधे बन जाते हैं तो उन्हें क्यारियों मे प्रत्यारोपित कर दिया जाता है. पौधे तैयार करने लिए जीवांशुयुक्त मिट्टी काफी उपयुक्त होती है, अतः पौधशाला (नर्सरी) की मिट्टी में कम्पोस्ट खाद अथवा गोबर की खाद भलीभाँति मिला दें. स्वस्थ एवं पुष्ट पौधे तैयार करने के लिए प्रतिवर्ग मीटर में 10 ग्राम अमोनियम फास्फेट तथा एक किलो सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें. रसभरी के पौधों की नर्सरी उठी हुई भूमि पर तैयार की जानी चाहिए. क्यारियाँ जमीन की सतह से लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर ऊँची होनी चाहिए.

क्यारियों का आकार: लगभग 3 मीटर लम्बा तथा 1 मीटर चौड़ा उपयुक्त माना जाता है. क्यारियों में बीज बोने के 20 या 25 दिन पश्चात् पौधे रोपण हेतु तैयार हो जाते हैं.

खाद तथा उर्वरक: भूमि परीक्षण के अनुसार ही पौषक तत्वों का प्रयोग करना चाहिये. रसभरी की उत्तम एवं स्वस्थ फसल प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पौषक तत्वों का प्रयोग अति आवश्यक है. एक हैक्टेयर में 20 टन गोबर की खाद या कम्पोस्ट खाद डालें. पौशक तत्व के रूप में 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटाश प्रति हैक्टेयर का प्रयोग करें. पौधे रोपण से तीन या चार सप्ताह पूर्व गोबर की खाद खेत में एक समान डालकर मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें, फास्फोरस तथा पोटाश की पूरी मात्रा व नाइट्रोजन की एक तिहाई मात्रा पौध रोपण से पूर्व खेत में डालें तथा नाइट्रोजन की शेष मात्रा दो बराबर भागों में विभाजित कर रोपा के 25 से 30 तथा 50 से 60 दिन के बाद की अवधि में क्यारियों में (खेत में) टॉपड्रैसिंग सग करें.

पौध रोपण: पौधों का रोपण 12 से 15 सेमी0 ऊँची क्यारियों में किया जाना चाहिए ताकि वर्षा की अवधि में खेत में बहते हुए पानी का सम्पर्क पौधों से न हो सके. यदि पानी का सम्पर्क पौधों से होता रहा तो उनकी जड़े गल जायेंगी और पूरी फसल नष्ट हो जायेगी. अतः खेत में जल निकासी का बंध किया जाना अत्यन्त आवश्यक है. रसभरी के पौधों का रोपण 5 जुला से पूरे अगस्त माह तक किया जा सकता है एवं रोपण दूरी 75 सेमी. X 75 सेमी. उपयुक्त है. पौध रोपण से तीन या पाँच दिन पूर्व पौधशाला में सिंचाई बन्द कर देना चाहिए.

खरपतवार नियंत्रण: खरपतवार पर नियंत्रण रखना आवश्यक है. अतः रसभरी की अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए समयानुसार खुरपी से तीन या चार बार खरपतवारों को निराई द्वारा समूल नष्ट करते रहना चाहिए.

सिंचाई: रसभरी की खेती के लिये अगस्त माह में जब अधिक वर्षा होती है तभी पौधरोपण की प्रक्रिया प्रारम्भ की जानी चाहिए क्योंकि पौध रोपण में गीली मिट्टी की आवश्यकता होती है. यही कारण है कि अगस्त माह पौधरोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है. पौध रोपण के 20 या 25 दिन पश्चात आवश्यकतानुसार सचा करते रहें.

प्रमुख रोग एवं कीट: (अ) जड़ गलन :- अधिक वर्षा होने के कारण रसभरी के पौधे जब निरन्तर जल के सम्पर्क में रहते हैं तो उनकी जड़ें गलने लगती है. इसी रोग को जड़ गलन रोग के नाम से जाना जाता है. इस रोग से पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खेत में पूर्व से ही जल निकासी की व्यवस्था करना अवाश्यक है. रोग नियंत्रण हेतु पौधों तथा जड़ो के आस-पास कार्बेन्डाजिम फफूंदनाशक 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहियें.

(ब) मोजैक :- रसभरी की खेती में बहुधा मोजैक का प्रकोप हो जाता है. इस रोग की रोकथाम के लिए प्रभावित पौधों को उखाड़कर मिट्टी में दबा दें तथा द्वितीयक संक्रमण को रोकने हेतु कीटनाशक जैसे लेम्डासाइलोथ्रिन (02 मिली0/ली0 पानी) का छिड़काव करे.

(स) लालरंग का कीट :- प्रायः सितम्बर माह के प्रारम्भ में लाल रंग के बहुत छोटे कीट का रसभरी की फसल पर प्रकोप दिखाई देने लगता है. यह कीट पत्तों की निचली सतह पर छुपा रहता है. इसके प्रकोप से फसल को बचाने के लिए लेम्डासाइलोथ्रिन कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए.

फलों की तुड़ाई: रसभरी के फल लगभग जनवरी से पकने लगते हैं. फलों का ऊपरी आवरण (छिलका) जब पीला हो जाता है तो समझना चाहिए के फल परिपक्व होने लगे हैं और उनकी तुड़ा का समय करीब है. रसभरी का फल पत्ते के पाश्र्व में घूमता हुआ नीचे की ओर लटक जाता है. ऐसी स्थिति में जबकि परिपक्व पीतवर्णी फल नीचे लटक गया हो तो उसे (फल को) सावधानीपूर्वक डंठल पकड़कर तोड़ना चाहिए.

पैकिंग एवं भण्डारण: रसभरी के फलों की पैकिंग इस प्रकार की जानी चाहिए की उनके बण्डलों में पर्याप्त मात्रा में हवा का आवागमन होता रहें. इसके लिए बाँस की डलियाँ, टोकरियाँ तथा प्लास्टिक क्रेटों का प्रयोग करना चाहिए. यदि पैकिंग सावधानीपूर्वक एवं भलीभाँति की गयी है तो रसभरी के फलों को 72 घण्टों तक बिना किसी संसाधन के सुरक्षित रखा जा सकता है.

भिलाई

अपनी क्रमवार बसाहट और हरियाली के लिए मशहूर भिलाई कभी देश का औद्योगिक तीर्थ कहलाता था. कभी यह संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा बचत प्लांट था. इस संयंत्र ने लगातार 11 बार सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र होने का प्रधानमंत्री अवार्ड जीता है. पर हकीकत यही है कि इस ऐतिहासिक शहर को अब दीमक चाट रही है. जिस संयंत्र की कार्य संस्कृति की दुहाई पूरी देश में दी जाती थी, अब वह ठेकेदारों का अखाड़ा बना हुआ है. भारत-रूस मैत्री की मिसाल इस संयंत्र के निजीकरण की सुगबुगाहट कोढ़ पर खाज का काम कर रही है.

उग रहे खण्डहर के टापू

» दीपक दास

परिवर्तन सृष्टि का नियम है. उद्योग व्यापार का पारिस्थितिकी तंत्र बदल रहा है. कोई भी उद्योग इससे अछूता नहीं है, फिर चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र ही क्यों न हो. भिलाई इस्पात संयंत्र पर भी इसका असर पड़ा. 1959 में एक मिलियन टन इस्पात निर्माण की क्षमता के साथ शुरू हुआ यह संयंत्र आज सात मिलियन टन की क्षमता प्राप्त करने के करीब है. जिस संयंत्र में कभी 65 हजार से अधिक नियमित कर्मचारी हुआ करते थे वहां आज केवल 16 हजार नियमित कर्मचारी हैं. शेष कार्य ठेकेदारों के जरिए सम्पन्न किये जा रहे हैं. इसका चौतरफा असर पड़ना लाजिमी था.

सार्वजनिक क्षेत्र के इस धड़कते इस्पाती भीम ने जहां देश की जड़ों को मजबूत किया वहीं एक बेमिसाल कार्यसंस्कृति को भी जन्म दिया. देश के कोने-कोने से अभियंता, शिक्षक, चिकित्सक और कार्मिक यहां आए और भिलाई को ही अपना घर बना लिया. वे सब आपस में ऐसे घुलमिल गए कि इस शहर को मिनी भारत की संज्ञा दे दी गई.

संयंत्र ने इस लघु भारत को बसाने में बड़ी भूमिका निभाई. इनके रहने के लिए सेक्टर बनाए गए. इसके एक छोर पर संयंत्र था तो दूसरे छोर पर विशाल सर्वसुविधायुक्त अस्पताल. सभी सेक्टरों में माध्यमिक तक शालाएं, प्रत्येक सेक्टर की पहुंच के भीतर स्वास्थ्य केन्द्र और हायर सेकण्डरी स्कूल स्थापित किये गये. अधिकांश सेक्टरों में बाजार स्थापित किये गये. संयंत्र संचालित स्कूलों में अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों के बच्चे साथ-साथ पढ़ते थे. इनकी गुणवत्ता की बदौलत ही इस शहर को एजुकेशन हब का तमगा मिला.

पर समय के साथ सबकुछ बदल गया. संयंत्र क्षेत्र में निजी स्कूल स्थापित होने लगे. डीपीएस के आने के बाद लगभग सभी अधिकारियों के बच्चे वहां शिफ्ट हो गए और बीएसपी ने अपने स्कूलों की तरफ ध्यान देना लगभग बंद हो गया.

एक शहर नहीं विरासत है भिलाई

भिलाई एक शहर मात्र नहीं है. यह देश के नवनिर्माण की विरासत है. यह भारत-रूस मैत्री का प्रतीक है. यह प्रतीक है उस मैत्री का जिस पर भरोसा करते हुए यूक्रेन ने भारत से मध्यस्थता की अपील की है. यह देश की वह मजबूत बुनियाद है जिस पर न केवल देश भर की ट्रेनें दौड़ती हैं बल्कि जिसका उपयोग युद्धपोत बनाने से लेकर दुर्गम क्षेत्रों में किया जाता है. यहां की कार्य संस्कृति, यहां का भाईचारा और यहां का साम्प्रदायिक सौहार्द्र बेमिसाल है. इसे यूं नष्ट नहीं होने दिया जा सकता.

नगर निगम की राह में भी रोड़ा

संयंत्र का आवासीय क्षेत्र भिलाई नगर पालिक निगम को हस्तांतरित हो चुका है. पर इसकी शर्तें ऐसी हैं कि निगम केवल पार्कों का सौन्दर्यीकरण ही कर पा रहा है. निगम क्षेत्र में पेयजल, निकासी, सड़क और बिजली जैसी मूलभूत जरूरतें उपलब्ध कराना निगम का भी दायित्व है. इसका मार्ग प्रशस्त किया जाना चाहिए.

दरअसल तेजी से गिर रही कार्मिकों की संख्या के कारण इतने सारे स्कूलों की जरूरत भी नहीं रहने वाली थी. एमजीएम, डीएवी, शंकराचार्य, श्री शंकरा, शारदा विद्यालय, स्वामी विवेकानंद, गुरुनानक स्कूल, जैसे निजी क्षेत्र के स्कूल तो थे ही.

बीएसपी के आज जो भी स्कूल बचे हैं वे अंग्रेजी माध्यम के हैं. बड़ी संख्या में स्कूल बिल्डिंग खण्डहर में तब्दील हो रहे हैं. इनमें से सेक्टर-6 के एक स्कूल को गरीब बच्चों के लिए भिलाई इस्पात विकास विद्यालय में तब्दील कर दिया गया तो एक अन्य को रिलायंस को सौंप दिया गया. शेष बंद पड़े स्कूलों के लिए कई प्रस्ताव आए पर संयंत्र ने कोई रुचि नहीं ली.

इसी तरह संयंत्र कर्मियों की कम होती संख्या के कारण आवासों की जरूरत भी कम हो गई. लिहाजा खण्डहर होते मकानों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया. खाली पड़े ये खण्डहर अब असामाजिक तत्वों का डेरा बन गया है. हाल ही में लिये गये एक फैसले में भिलाई इस्पात संयंत्र ने अपने कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए सुरक्षित आवास का रास्ता खोल दिया है.

भिलाई इस्पात संयंत्र में सक्रिय श्रमिक संगठनों ने भी कभी टाउनशिप की सुध नहीं ली. उन्होंने स्वयं को एनजेसीएस की बैठकों, वेतन और भत्तों तक ही सीमित रखा. अब जाकर श्रमिक यूनियन ने सात मिलयन टन परियोजना के तहत भर्ती हुए 2400 कार्मिकों के लिए उपयुक्त आवास की मांग उठाई है. पर अब उनकी सुनने वाला कोई नहीं है.

लगातार कम होती श्रमिक संख्या की मार स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ी है. सेक्टर-9 का पं. जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केन्द्र अपनी बदहाली पर रो रहा है. स्टील सिटी के इस सबसे बड़े अस्पताल में न्यूरोसर्जरी, इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी जैसे विभाग अपंग हो गए हैं. डाक्टरों और नर्सों की संख्या लगातार कम हो रही है. मरीज निजी अस्पतालों को रिफर किये जा रहे हैं. संयंत्र के अस्पतालों पर आश्रित अवकाश प्राप्त कर्मचारियों की शामत आई हुई है.

एक दशक पहले भी पं. जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केन्द्र को मेडिकल कालेज बनाने की बातें होती थीं. इस अस्पताल को एनएबीएच सर्टिफिकेशन दिलाने के लिए भी प्रयास किये गये. पर कोई भी कोशिश परवान नहीं चढ़ी. अब यह केवल एक बड़ा मैटर्निटी सेन्टर बन कर रह गया है.

किसी भी टाउनशिप की सबसे बड़ी सुविधा वहां की पेयजल और निकासी व्यवस्था होती है. संयंत्र के टाउनशिप में ये दोनों ही व्यवस्था चरमरा गई है. दशकों पुरानी पाइप लाइन सड़ चुकी है. पेयजल की जगह गंदा पानी आ रहा है. हंगामा भी हुआ पर किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी. समय के साथ अधिकांश घरों में आरओ वाटर प्यूरीफायर लग गया और लोंगों ने हंगामा करना भी बंद कर दिया.

संयंत्र की भलमनसाहत का शासकीय सेवकों और जनप्रतिनिधियों ने बेजा फायदा उठाया है. कार्यकाल के दौरान संयंत्र ने गुडविल के तहत जो मकान उन्हें दिया उसे उन्होंने अपनी संपत्ति समझ लिया. मजबूर संयंत्र प्रशासन ने थोड़े ही दिन पहले एक पूर्व विधायक का सामान क्वार्टर से बाहर फेंकवा दिया. 32 बंगला से एक अपदस्थ नेता को निकालने के लिए भी अनेक पापड़ बेलने पड़े थे. सेक्टर-4 के एक मकान को खाली कराने की कोशिशें हुई तो तीन जवान बेटियों के साथ मां ने क्वार्टर में ही जहर खाकर अपने प्राण त्याग दिए.

यह कर सकता है संयंत्र प्रशासन

अनुपयोगी क्वार्टरों को किराए पर चढ़ाने के लिए स्पष्ट नीति बनाए और इसकी आउटसोर्सिंग कर दे. इसमें कोई समस्या हो तो उसे भिलाई नगर पालिक निगम को सौंप दे.

अनुपयोगी स्कूलों, हाईस्कूलों को

पीपीपी मॉडल पर दिया जा सकता है. इनमें व्यवसायिक शिक्षा के केन्द्र खोले जा सकते हैं. कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने इसका प्रस्ताव भी दिया था पर बात आई गई हो गई. इससे न केवल संपत्ति की सुरक्षा होगी बल्कि अच्छी खासी कमाई भी हो सकती है. फिलहाल सेक्टर-6 में रिलायंस का एक केन्द्र संचालित है. अस्पतालों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए निजी क्षेत्र के साथ एमओयू किया जा सकता है. इससे ओपीडी और आईपीडी दोनों में सुधार होगा. एंजियोग्राफी/एंजियोप्लास्टी, न्यूरोसर्जरी जैसी सुविधाएं सुचारू हो जाएंगी. अस्पताल की शानदार अधोसंरचना, लोकेशन और अन्य आनुषांगिक सुविधाओं का दोहन हो पाएगा.

स्थायी परिपत्र तैयार करने की आवश्यकता

राज्य शासन को चाहिये कि प्रबंधन के साथ मिलकर भूमि भवनों की स्थिति पर एक स्थायी परिपत्र तैयार करे. शहरी विकास अभिकरण के सहयोग से इस शहर के ऐतिहासिक गौरव को पुनर्स्थापित करने की कार्ययोजना बनाए. खण्डहर होते भवनों की जीर्णोद्धार कर केन्द्र और राज्य सरकारों की गरीब कल्याण व आवास योजनाओं की मदद करे.

मानवता के पर्याय बने वाडेकर

कोरोना काल में 588 शवों का अंतिम संस्कार कर मानवता का परिचय देने वाले भूपेन्द्र वाडेकर ने लोगों की दिलों में जगह बनाई और नया उदाहरण समाज में प्रस्तुत किया.

कोरोना वायरस का संक्रमण इतना फैल चुका था कि केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों को देशभर में लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ गई. लोग संक्रमण से बचने के लिए घरों में कैद हो गए. सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा. अगर किसी मोहल्ले में कोई कोविड संक्रमित मरीज मिल जाता, तो सभी उस परिवार से दूरी बना लेते थे. संक्रमण का भय लोगों के चेहरे में तब देखने को मिला, जब असमय लोगों की मौत होनी शुरू हुई. ऐसे वक्त में मृतक के परिवार के सदस्य भी शव को हाथ नहीं लगा रहे थे. दूसरी ओर कोविड प्रोटोकाल के चलते प्रशासन भी शव को परिजनों को नहीं सौंपती थी. यह कोविड काल की सबसे मुश्किल घड़ी थी, और ऐसे वक्त में नगर निगम के समाज कल्याण विभाग राजनांदगांव के अधिकारी भूपेन्द्र वाडेकर को शव के अंतिम संस्कार कराने की जिम्मेदारी सौंपी. समाज कल्याण अधिकारी श्री वाडेकर ने भी साहस का परिचय देते हुए इस युद्ध में आगे बढ़ते चले गए. जब वातावरण में कोविड की दूसरी लहर आई तो संक्रमण से मरने वालों की संख्या एक ही दिन में 20 से 25 थी. इस समय भी श्री वाडेकर ने अपनी टीम के साथ साहस का परिचय देते हुए संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार किया. श्री वाडेकर ने छत्तीसगढ़ आजतक संवाददाता को बताया कि मुक्तिधाम में लगातार शव आ रहे थे. पूरे मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार करने के लिए भी जगह नहीं थी. चिताओं की आग और राख से पूरा मुक्तिधाम परिसर भर गया था. उन्होंने बताया कि सुबह जब आंख खुलती, तो बस एक ही दुआ करते थे कि आज किसी की भी मौत कोविड से न हो. दूसरी ओर इस मुश्किल दौर में परिवार वालों और रिश्तेदारों का भी चिंता रहता था कि अपनी जिम्मेदारी के चलते इस महामारी का सामना कहीं उनको न करना पड़ जाए. महामारी के दौरान हमारी पूरी टीम ने 588 शवों का अंतिम संस्कार कर मानवता का परिचय दिया. समाज कल्याण अधिकारी श्री वाडेकर ने दुख के समय क्षेत्र के लोगों के लिए एक परिजन बनकर जो साहस का काम किये उससे उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली.

श्रीराम और माता सीता यहां शिवनाथ और खारून के संगम के आसपास टहला करते थे. संगम की रेत से प्रभु श्रीराम ने शिवलिंग का निर्माण किया था. माता सीता स्वयं प्रतिदिन इसकी पूजा करती थीं.

तिल-तिल बढ़ रहा सोमनाथ का शिवलिंग

श्रीराम ने किया था स्थापित

» संतोष यादव

विश्वप्रसिद्ध सोमनाथ के मंदिर के बारे में तो हम सभी जानते हैं. पर एक सोमनाथ का मंदिर अपने छत्तीसगढ़ में भी है. खारून-शिवनाथ संगम पर स्थित इस मंदिर में एक अद्भुत बालुका शिवलिंग है. मान्यता है कि इस शिवलिंग का निर्माण स्वयं प्रभु श्रीराम ने किया था. वनवास काल में माता सीता के साथ उन्होंने यहीं संगम पर कुछ समय व्यतीत किया था. इस शिवलिंग का आकार तिल-तिल कर बढ़ रहा है. अभी यह लगभग साढ़े तीन फीट का है.

छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में रायपुर-बिलासपुर मार्ग पर भूमिया-सांकरा नामक गांव हैं. रायपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर इन गावों के पश्चिम में है ग्राम लखना. लखना की सीमा पर शिवनाथ नदी एवं खारुन नदी का संगम होता है. संगम किनारे एक ऊंचे टिले पर सोमनाथ शिव का प्राचीन मंदिर है. यहां स्थापित स्वयं भू शिवलिंग का आकार धीरे-धीरे बढ़ रहा है. साल में 3 बार ठंड, गर्मी और बरसात के मौसम में शिवलिंग का रंग बदल जाता है. कभी यह काला होता है, कभी भूरा हो जाता है तो कभी हल्के चाकलेटी लाल रंग का हो जाता है.

किंवदंती के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्रीराम ने अपने वनवास का काफी वक्त छत्तीसगढ़ (तत्कालीन कोसल) राज्य में बिताया था. श्रीराम और माता सीता यहां शिवनाथ और खारून के संगम के आसपास टहला करते थे. संगम की रेत से प्रभु श्रीराम ने शिवलिंग का निर्माण किया था. माता सीता स्वयं प्रतिदिन इसकी पूजा करती थीं. 7वीं-8वीं शताब्दी में यहां मंदिर का निर्माण कराया गया. वर्तमान में यहां कई मंदिर हैं. मंदिर के पीछे दक्षिण से खारून नदी आती है और पश्चिम से आ रही शिवनाथ में मिल जाती है. यहां नदी का पाट काफी चौड़ा है. घाट पर संकरी डोंगियों की कतार लगी रहती है. दर्शनार्थी इन डोंगियों में बैठकर संगम की यात्रा करते हैं. आसपास प्राकृतिक छटा बिखरी हुई है. बड़ी संख्या में लोग यहां पिकनिक मनाने आते हें. पेड़ों की छांव में बैठते, भोजन करते हैं. बच्चे आसपास लगे झूलों का आनन्द लेते हैं. यहां लंगूर के भी दर्शन हो जाते हैं. पर ये लंगूर किसी को परेशान नहीं करते.

संगम के मध्य एक मंदिर है, जहाँ शिवलिंग व हनुमान की मूर्तियाँ हैं. सोमनाथ तीर्थ स्थल छत्तीसगढ़ का एक मनोहारी पर्यटन स्थल है.

स्कूल कालेजों में पुलवामा शहीदों का पुण्यस्मरण किया गया. यह आयोजन कहीं ऑनलाइन, कहीं ऑफलाइन तो कहीं ब्लेंडेड मोड में हुआ. पुलवामा में जवानों की शहादत को तीन बरस गुजर गए. 2019 में 300 किलो आरडीएक्स से लदे एक वाहन ने सेना के काफिले को अपनी चपेट में ले लिया था. इस आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे. देश जवानों की यह कुर्बानी भूला नहीं है, न ही कभी भूल पाएगा. कुछ सवाल हैं जिनका जवाब उसे आज भी नहीं दिया गया है.

तीन साल बाद भी नहीं मिले पुलवामा चूकों के जवाब

विस्फोटकों से हमले की थी पूर्व सूचना

राष्ट्र का भावनात्मक दोहन करती रही सरकार

माना कि देश की सुरक्षा के लिए तैनात जांबाजों का जीवन हमेशा जोखिम में होता है पर इनकी सुरक्षा के न्यूनतम उपाय करना हमारा नैतिक दायित्व है. इन उपायों में जवानों को बेहतर सुरक्षा उपकरण, आधुनिकतम असलहा और बेहतर लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल है. जब-जब इसमें चूक होती है राष्ट्र खून के आंसू रोता है. कोशिश यह होनी चाहिए कि हम इन चूकों से सबक लें, इन चूकों को न दोहराने का संकल्प लें, न कि इनपर पर्दा डालने की कोशिश करें.

'पुलवामा के शहीदों को हम कभी भुला नहीं सकते. उनका व उनके परिवारों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा. हम जवाब लेकर रहेंगे. जय हिंद!"

- राहुल गांधी

पहला सवाल

पुलवामा हमला हाई-सिक्योरिटी जोन में हुआ था. यह वह इलाका है जहां आम लोग भी बिना जांच पड़ताल और पूछताछ के प्रवेश नहीं कर सकते. फिर कैसे 300 किलोग्राम आरडीएक्स से लदा वाहन इस इलाके में प्रविष्ट हो जाता है और वह सेना के काफिले तक पहुंच जाता है?

दूसरा सवाल

पुलवामा हमले के तुरन्त बाद यह बात सामने आई थी कि खुफिया तंत्र ने इसकी पूर्व सूचना दी थी. ऐसी 11 सुरक्षा इनपुट्स जिम्मेदारों को मिली थी. 'फ्रंटलाइन' ने इस पर विस्तार से रिपोर्ट प्रकाशित की थी. इन सूचनाओं में यह आशंका जताई गई थी कि सेना की टुकड़ी पर विस्फोटकों के द्वारा हमला किया जा सकता है. इस चेतावनी का, इन सूचनाओं का जिम्मेदार लोगों ने क्या उपयोग किया, इसका कोई जवाब राष्ट्र को अब तक नहीं दिया गया है.

तीसरा सवाल

स्थानीय पुलिस को भी ऐसे किसी हमले की पूर्व सूचना थी. पुलिस ने इस सूचना का क्या किया, इसका कोई जवाब आज तक सामने नहीं आ पाया है. क्या पुलिस ने बैरिकेडिंग कर वाहनों की जांच की? क्या उसने इस सूचना को किसी से साझा किया?

संसद में उठा सवाल

जब इस घटना को लेकर संसद में पत्रकारों ने सवाल उठाए तो सेनाध्यक्ष केवल इतना ही कह पाए कि राष्ट्र तैयार है और इसका जवाब दिया जाएगा. सूरक्षा चूकों पर कोई टिप्पणी करने से उन्होंने साफ इंकार कर दिया.

राजनीतिक उपयोग

पुलवामा शहादत का खुलकर राजनीतिक उपयोग किया गया. इस घटना का हवाला देकर राष्ट्र का भावनात्मक दोहन किया गया. स्वयं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पुलवामा शहीदों के नाम पर जनता का समर्थन मांगा. उन्होंने कहा –"मैं अपने फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूँ, कि आपका पहला वोट, पुलवामा में जो वीर शहीद हुए हैं, उन वीर शहीदों के नाम, आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या?"

आपके बच्चों के पढ़ाई-लिखाई से संबंधित सारी समस्याओं का एक समाधान

DMIT

(Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test)

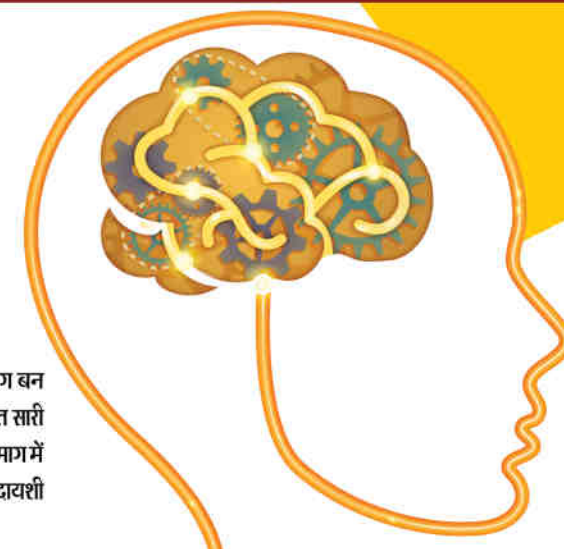

बच्चा आपका उसका कैरियर बनाने का तरीका हमारा

बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है 13 से 21 सप्ताह में उसका दिमाग बन जाता है तथा ठीक उसी समय उसके फिंगर प्रिंट्स भी बन जाते हैं. बहुत सारी वैज्ञानिक खोजों के द्वारा यह साबित हो चूका हैं कि फिंगर प्रिंट्स एवं दिमाग में बहुत बड़ा सम्बन्ध है. इनकी सहायता से किसी भी व्यक्ति की पैदायशी प्रतिभायों को जाना जा सकता है.

क्या आप जानना चाहते है

आपके बच्चे के अंदर कौन सा है टैलेन्ट?

ठीक ? क्योंकि आप अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और अपने बच्चों की सभी जरूरतों के बारे में पूर्णतया समझते हैं...

DMIT क्यों ?

- क्या आप जानते हैं की भारत में प्रतिवर्ष 12000 से अधिक स्टूडेंट्स परीक्षा सम्बंधित तनाव के कारण आत्महत्या करते हैं ?
- क्या आप जानते हैं की एक दो साल का बच्चा भी तनाव का शिकार हो सकता है?
- बचपन अब बच्चों का खेल नहीं है और आप सोचते हैं की यह आपके बच्चे के साथ नहीं हो सकता ?

कोई भी लंबा शब्द या अनुक्रम का नंबर जल्दी कैसे याद रखें।

MEMORY बड़े या मुश्किल सवालों के जवाब कैसे याद रखें।

Yeeshu Sir
Mind Trainer, DMIT Counselor
Hypnotherapist

एक सुनहरा मौका

बने Trainer व Counselor

और कमायें 50 हजार से 1 लाख तक प्रति माह

अगर आप किसी कंपनी से रिटायर्ड व्यक्ति है, नेटवर्क मार्केटिंग से हो चुके है निराश
Govt./प्राईवेट जॉब कोई नया व्यवसाय की है तलाश, तो अभी कॉल करें

फ्रेंचायसी एवं सेमिनार के लिए संपर्क करें

MIND TRAINING ACADEMY

Risali, Bhilai, Distt.: Durg(C.G.) Mob.: 7880003262

एक-एक रुपये दान कर बनाया शिवालय

खारून नदी- सोनपुर नाला संगम मध्य ठकुराइन टोला का विशाल शिवालय

शिवलिंग स्थापना की कथा अनूठी

निषाद समाज मंदिर में भगवान राम के चरण पखारते गुहा निषादराज की प्रतिमा स्थापित करना प्रस्तावित था. वर्ष 1980-81 में मंदिर निर्माण कार्य चल ही रहा था कि खारून नदी में अचानक बाढ़ आ गई. बाढ़ का पानी उतरा तो ग्रामीणों ने देखा कि मंदिर की सीढ़ियों में एक बैल के ऊपर चढ़ने के निशान हैं परंतु उतरने के नहीं. लोगों में यह माना कि भगवान शिव का वाहन नंदी यहां आया था और चबूतरे में आराम करने के बाद अंर्तध्यान हो गया. इस भावना के चलते ही सर्वसम्मति से मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की गई. कालांतर में मंदिर की दीवार पर भगवान राम- गुहा निषादराज वाला म्यूरल उकेरा गया.

टोलाघाट संगम का शिव मंदिर सामाजिक समरसता का केंद्र

छत्तीसगढ़ का एक गढ़ है पाटन. यहां से महज छह किमी की दूरी पर खारुन नदी व सोनपुर नाला के संगम पर स्थित है 36 साल पुराना शिव मंदिर. यह स्थल सामाजिक समरसता के संगम के साथ-साथ बेहतर पिकनिक स्पॉट और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए चर्चित हो चुका है. 74 फीट ऊंचे इस मंदिर का निर्माण हर घर से एक-एक रुपए चंदा लेकर तथा श्रमदान कर 12 पाली निषाद समाज द्वारा 52 वर्षों में किया गया है. शिव मंदिर टोलाघाट को छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के नक्शे में शामिल करने यहां लक्ष्मण झूला बनाने का निर्णय लिया गया है.

» हेमंत कश्यप

बारह पाली ने किया निर्माण

दुर्ग से 33 किमी दूर तहसील मुख्यालय पाटन है. पाटन से सिकोला होकर रायपुर जाने वाले मार्ग पर छह किमी दूर खारुन नदी और सोनपुर नाला के संगम स्थल पर ठकुराइन टोला नामक गांव है. ठकुराईन टोला, परसदा, आमदी, कन्हेरा, टेकारी, खट्टी, ढोर्रा, लमकेनी, सुपकोन्हा, सोनपुर, खमरिया, डंगनिया, पाटन, अटारी, खट्टी, बठेना, चंगोरी, चीचा, तुलसी, खुड़मुड़ी, पेण्ड्री और सेलूद सहित 22 गांवों में निषाद समाज के लगभग 700 परिवार निवासरत हैं. निषाद समाज इन गांवों में बसे स्वजातियों की एकजुटता को 12 पाली के नाम से संबोधित करता है. पूर्व जनपद सदस्य चिंताराम निषाद बताते हैं कि समाज के लोगों को रायपुर

के हटकेश्वर शिवालय महादेव घाट रायपुर और राजिम के कुलेश्वर मंदिर से टोलाघाट में मंदिर बनाने की प्रेरणा बियानबे साल पहले 1930 में मिली थी.

तन-मन-धन से बना मंदिर

बताया जाता है कि वर्ष 1930 में निषाद समाज की पहली बैठक ठकुराईन टोला में हुई थी. जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि मंदिर निर्माण के लिए 22 गांवों में बसे निषाद समाज के लोग प्रत्येक घर से सालाना एक रुपये चंदा देंगे तथा प्रत्येक गांव क्रमबद्ध श्रमदान करेगा. इस निर्णय के बाद वर्ष 1931- 32 में टोलाघाट स्थित संगम में मंदिर बनाने नींव डाली गई थी. समाज के पहले अध्यक्ष बुधराम निषाद (परसोदा), महामंत्री माहरूराम निषाद (खट्टी), कोषाध्यक्ष पचकौड़ निषाद (ठकुराइन टोला)थे. लगातार 52 वर्षों तक मंदिर निर्माण कार्य चलता रहा और फरवरी 1984 में पूर्ण हुआ. मंदिर निर्माण के बाद भी 12 पाली में बसे निषाद समाज के लोग प्रतिवर्ष 12 रुपये वार्षिक चंदा दे रहे हैं. इतना ही नहीं जिसके घर में विवाह होता है. वह भी मंदिर के लिए सौ रुपये अनिवार्य रूप से भेंट करता है. बताया गया कि मंदिर निर्माण से लेकर सामाजिक भवन निर्माण तक एक करोड़ पैंतालीस हज़ार रुपये से अधिक की राशि खर्च हो चुकी है.

नदी तट विराजे देवी-देवता

वर्ष 1984 में संगम में शिव मंदिर पूर्ण होने के बाद खारुन नदी के तटों पर विभिन भक्तों द्वारा देवी-देवताओं के 15 से अधिक मंदिरों का निर्माण करवाया गया है. कुर्मी समाज द्वारा राम मंदिर, यादव समाज ने कृष्ण मंदिर, गोपाल वर्मा द्वारा एकादश मंदिर, पंजाब सनातन सभा ने गुरुद्वारा, साहू समाज द्वारा कर्मामाता मंदिर एवं धर्मशाला. इसके अलावा श्रीधर निषाद (खट्टी), दशरथ साहू, फूलसिंह साहू, सुंदरलाल साहू, संतराम सिन्हा व हृदयराम द्वारा शिव मंदिर बनवाया गया है. इसके अलावा खेदूराम निषाद ने रामेश्वर, लीलाराम निषाद ने काली और भैरव, गोंड आदिवासी समाज द्वारा बूढ़ादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया है. शिवालय के ठीक नीचे नंदीराज की विशाल प्रतिमा भी स्थापित की गई है. अन्य समाज के लोग भी शिव मंदिर संवर्धन हेतु स्वेच्छा से दान करते आ रहे हैं.

दर्शनीय है टोलाघाट

खारुन नदी और सोनपुर नाला के संगम पर निर्मित शिव मंदिर लोगों को बरबस राजिम में महानदी-पैरी और सोंढूर नदी के संगम पर दृढ़ता से खड़े कुलेश्वर मंदिर की याद दिलाता है. लोग टोलाघाट को दूसरा राजिम मानने लगे हैं. बारिश के दिनों में जब बाढ़ का पानी मंदिर के चबूतरे को डूबोने लगता है. तब ऐसा प्रतीक होता है जैसे कोई रथ पानी के ऊपर चल रहा है. लोग इस दृश्य को देख सम्मोहित रह जाते हैं. यहां प्रति वर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर मेला आयोजित किया जाता है. मेला व्यवस्था शिव मंदिर समिति करती है. टोलाघाट में प्रति वर्ष सैकड़ों प्रवासी पक्षी भी आते हैं. इन मेहमानों की सुरक्षा ग्रामीण स्वयं करते हैं. इन सब के चलते लोग बड़ी संख्या में पिकनिक मनाने यहां आते हैं. टोलाघाट आने के लिए रायपुर, दुर्ग, अभनपुर आदि स्थानों से पक्की सड़कें हैं. क्षेत्र के अधिकांश लोग राजिम न जाकर टोलाघाट संगम में अपने प्रियजनों की अस्थियां विसर्जित करने लगे हैं. टोलाघाट की प्रसिद्धि तेजी से बढ़ी है इसलिए शिव मंदिर टोला घाट प्रक्षेत्र को छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के नक्शे में शामिल कर इसे बेहतर पर्यटन स्थल के रुप में विकसित करने की मांग भी उठ रही है.

पवन दीवान ने की थी प्राण प्रतिष्ठा

संगम में पहले बड़े- बड़े शिलाखंडों से 24 फीट ऊंचा मजबूत चबूतरा बनाया गया. तत्पश्चात उस पर 50 फीट ऊंचा शिवालय तैयार किया गया है. विक्रम संवत 2040 की महाशिवरात्रि (वर्ष 1984) को इस शिवालय में छत्तीसगढ़ के संत- कवि पवन दीवान ने शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की थी. इस मौके पर टोला घाट में पहला तीन दिवसीय महाशिवरात्रि मेला आयोजित किया गया था. अब इस मंदिर परिसर में विभिन्न देवी-देवताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित कर ली गई हैं. मंदिर का संचालन निषाद समाज 12 पाली द्वारा ही किया जा रहा है.

देश के विभिन्न सिनेमाघरों में एक महीना से अधिक समय तक चलने वाली दक्षिण भारतीय फिल्म पुष्पा और उसका गीत स्वामी स्वामी... ने खूब तहलका मचाया. गीत को सुन-देखकर बस्तरवासी इस बात को लेकर खुश है कि गीत के फिल्मांकन में बस्तर की परंपरागत बंदी धोती का उपयोग अभिनेत्री और सह कलाकारों ने किया है. बताते चलें कि बंदी धोती बस्तर में खासकर धुर्वा आदिवासी समाज में काफी लोकप्रिय है. एक बंदी धोती डेढ़ हजार रुपए से लेकर दो हजार रूपये तक में मिलती है.

ग्राम सड़क योजना का अनाथों जैसा हाल

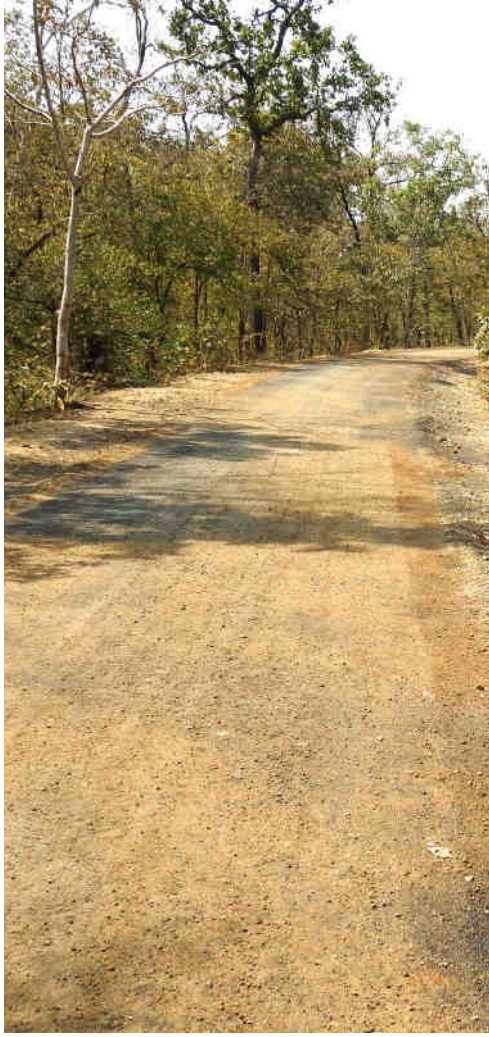

फोटो : पी. मोहन

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की हालत अनाथों जैसी हो गई है. वह जिये या मरे इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. सड़कों के नाम पर कई मालामाल हो गए पर सड़कें कुपोषित ही रह गईं. इनमें से कुछ ने तो समय से पहले ही दम तोड़ दिया. पांच साल तक संधारण की शर्त में बंधा होने के बाद भी ठेकेदार बिंदास हैं. अधिकारी उसकी जेब में हैं और जिम्मेदारों का खर्चा पानी उसने बांध ही रखा है. सरकार इन घटिया सड़कों का किलोमीटर नापकर ही खुश है. मानपुर और आंधी क्षेत्र की पांच सड़कों का निरीक्षण करने पर यह सच उजागर हुआ है. लगभग यही स्थिति पूरे राज्य की है.

मानपुर ब्लॉक के पांच सड़कों का बुरा हाल

शासन की महत्वाकांक्षी योजना को लगा पलीता

शिकायतों की भी नहीं होती सुनवाई

» छ.ग. आजतक ब्यूरो

भारत सरकार ने 25 दिसंबर 2012 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी. इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में 500 या इससे अधिक आबादी वाले (पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 लोगों की आबादी वाले) सड़क-संपर्क से वंचित गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना है. भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य क्षेत्रों में 1000 या उससे अधिक आबादी वाली बसाहटें तथा आदिवासी क्षेत्रों में 500 या उससे अधिक आबादी वाली बसाहटों को बारामासी सड़क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. इसके अलावा सभी बाजार हाट केन्द्रों, चिकित्सा केन्द्रों एवं उच्च शिक्षा केन्द्रों को जोड़ने का कार्य भी इसी अवधि में पूर्ण किया जाना है.

योजना प्रारंभ के समय छत्तीसगढ़ में तो सिर्फ 17 प्रतिशत के लगभग गांव बसाहटें ही डामरीकृत सड़कों से जुड़ी हुई थी. 2016 तक यह प्रतिशत बढ़कर 76 प्रतिशत हो गई थी. वर्ष 2002 में मास्टरप्लान तैयार करते समय छत्तीसगढ में कुल 29544 बसाहटें चिन्हित की गयी थी. 2006 में मास्टरप्लान का पुन: परीक्षण कराया गया जिसमें यह संख्या 27606 आंकी गई.

ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार द्वारा 09 अप्रैल 2014 को नक्सल प्रभावित 07 जिलों के 29 विकासखण्डों का चयन करते हुए इन विकासखण्डों में 100 से 249 जनसंख्या वाली बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने हेतु स्वीकृति दी.

ऐसी बननी थी सड़क

विधायक हुए आगबबूला

इन सड़कों की हालत को जब मोहला-मानपुर विधायक इंदरशाह मण्डावी की संज्ञान में लाया गया तो वे आगबबूला हो गए. उन्होंने तत्काल कार्यपालन अभियंता को फोन लगाकर उन्हें जमकर फटकार लगाई. उन्होंने कहा कि वे अपने क्षेत्र में घटिया निर्माण बर्दाश्त नहीं करेंगे. विधायक वे कार्यपालन अभियंता को तत्काल स्वयं जाकर सड़कों की जांच करने को कहा. साथ ही यह अल्टीमेटम भी दिया कि यदि जांच रिपोर्ट तत्काल नहीं मिली तो वे अपना आदमी भेजकर निर्माण की गुणवत्ता की परख करवाएंगे. साथ ही ईई की शिकायत ऊपर लेवल पर करेंगे.

नये दिशा-निर्देशानुसार जिन सड़कों में 100 वाहन से कम आवागमन है वहां डामरीकृत सतह की चौड़ाई 3.00 मीटर तथा जिन सड़कों में 100 वाहन से अधिक आवागमन है वहां सड़कों की चौड़ाई 3.75 मीटर किये जाने का प्रावधान है. दोनों स्थितियों में सड़क की ऊपरी चौड़ाई 6.00 मीटर ही रखा जाना है. पर इसमें जमकर भ्रष्टाचार किया गया. सड़क निर्माण की बुनियादी शर्तों का ही पालन नहीं हो पाया. सड़कें समय से पहले ही टूट गईं या उखड़ गईं या फिर उसमें दरारें पड़ गईं. जिस उद्देश्य को लेकर इन सड़कों का निर्माण किया जाना था, वही खूंटे पर टंग गया.

मोहला क्षेत्र की पांच सड़कें खराब

मोहला की तीन ग्रामीण सड़कों का ठेका राजनांदगांव के ठेकेदार राकेश गुप्ता ने लिया है. ये सड़कें रेंगाटोला से गहनगट्टा, बागडोंगरी से घोटियाकन्हार तथा पेंदोड़ी से डोरके तक बन रही हैं. सड़क निर्माण के लिए स्तरहीन सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है. भुरभुरी गिट्टी, मिट्टी जैसा मुरुम और काले जले तेल जैसा डामर. सड़कें नहीं बन रहीं, मजाक हो रहा है. शासन की मंशा को पलीता लगाया जा रहा है. इस क्षेत्र की ज्यादातर सड़कें 30 से 40 प्रतिशत अतिरिक्त दर (above) पर ली गई है. शारदा से आम्रपैली सहित औंधी क्षेत्र के कई सड़कें लैंड मार्क एसोसिएट कंपनी दिल्ली द्वारा बनाई गई है जो जर्जर हालत में है. इसी तरह राजस्थान एसोसिएट रायपुर द्वारा नवागांव से बागडोंगरी मार्ग को 30 प्रतिशत अतिरिक्त दर पर बनाई गई है. तीन किमी की यह सड़क खराब हो चुकी है. राजनांदगांव के ठेकेदार राकेश गुप्ता द्वारा बागडोंगरी से घोटियाकन्हार 3.40 किमी और मेघाबुजुर्ग से तुकाम 3.65 किमी की सड़क जिसकी लागत 4 करोड़ रुपए एवं पेंदोड़ी से डोड़के (नैनगुड़ा) 5.85 किमी 25 प्रतिशत अतिरिक्त राशि में ली गई है. पर ये सभी सड़कें गुणवत्ताहीन है. निर्माण के 15 दिनों बाद सड़कें सामान्य हाथों से उकेलने पर उखड़ रही हैं.

विसंगतियों की जड़

सड़क का ठेका लेने वाले बड़े ठेकेदार इस कार्य में रुचि नहीं लेते. वे ग्रामीणों को ही पेटी पर काम दे देते हैं. इन्हें भुगतान तब किया जाता है जब शासन से पैसा मिलता है. इसमें लेट लतीफी हुई तो खामियाजा गरीब ग्रामीण मजदूर व छोटे ठेकेदार ही भुगतता है. ग्राम तुकाम, बागडोंगरी, घोटियाकन्हार के ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें 200 रुपए रोजी पर काम दिया गया था पर महीनों बीतने के बाद भी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है. इसी तरह कई पेटी कांट्रेक्टरों का भुगतान अटका पड़ा है.

यह थी शासन की मंशा

अच्छी सड़कों के बिना गांव की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति की कल्पना नहीं की जा सकती. सड़कें बनने पर न केवल किसानों के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे बल्कि कृषि उपज को बाजार तक पहुंचाना भी सहज हो जाएगा. यही नहीं बीमार पड़ने की स्थिति में एम्बुलेंस भी गांव तक जा सकेंगे. अभी हाल यह है कि लोग खटिया पर मरीज को लेकर मीलों पैदल चलकर उसे सड़क तक लाते हैं. इस विलम्ब के कारण अनेक रोगियों की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मृत्यु हो जाती है.

इन पर है क्रियान्वयन की जिम्मेदारी

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग को इस योजना को अमलीजामा पहनाने का दायित्व सौंपा गया है. राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण का गठन किया गया है. इसके अतिरिक्त

क्षेत्रीय स्तर पर 8 मंडल कार्यालय एवं जिला स्तर पर 34 समर्पित परियोजना क्रियान्वयन इकाई हैं. दिलचस्प यह है कि छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की जिम्मेदारी एक आईएफएस अधिकारी आलोक कटियार को सौंपी गई है जिनका सड़क निर्माण से दूर-दूर तक कोई रिश्ता नहीं है. राजनांदगांव और मानपुर मोहला जिलों में कार्यसंपादित कराने की जिम्मेदारी सिंचाई विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आए पीपी खरे को सौंपी गई है. श्री खरे इससे पहले कवर्धा में तैनात थे. वहां भी उनकी कार्यशैली सवालों के घेरे में रही है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कवर्धा जिला मुख्यालय से सटे गांव मजगांव से सैगोना में सीसी रोड का निर्माण किया गया. निर्माण के छह माह के भीतर ही रोड पर बड़ी-बड़ी दरारें आ गई. तब लोगों ने इसका जमकर विरोध किया था.

भारी भरकम गुणवत्ता नियंत्रण, नतीजा सिफर

गुणवत्ता नियंत्रण हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था की गयी है इसके बावजूद नतीजा सिफर है. गुणवत्ता सुनिश्चित करने जिला स्तर पर परियोजना क्रियान्वयन इकाई हैं. इनकी सहायता के लिए सलाहकार भी. राज्य स्तर पर सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को राज्य गुणवत्ता समीक्षक नियुक्त किया गया है. राष्ट्रीय स्तर पर अन्य राज्यों के सेवानिवृत्त वरिष्ठ अभियंता जो अधीक्षण अभियंता एवं उच्च पद पर पदस्थ रहे हों, को स्वतंत्र समीक्षा

हेतु राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक के रूप में भेजा जाता है. प्रत्येक जिले में सामग्री परीक्षण प्रयोग शालाएं स्थापित की गयी हैं. राज्य स्तर पर केन्द्रीय प्रयोगशाला तथा 26 चलित सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला भी स्थापित की गयी है.

जाहिर है ये इकाइयां अपना काम नहीं कर रहीं. मुख्यमंत्री तक की गई शिकायतों का ठंडे बस्ते में चला जाना, अकेला यह बताने के लिए काफी है कि सबको फ्री-हैण्ड है. शिकायतें होती हैं, जिम्मेदारों की टेबल तक पहुंचती भी हैं पर उनपर कोई कार्यवाही नहीं होती. जाहिर है कि सबकी मिलीभगत से इस महत्वाकांक्षी योजना को पलीता लगाया जा रहा है. जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा कुछ लोगों की जेबों में जा रहा है.

LAXMI Sky Life
Laxmi GROUP
Trust & Quality
CHHATTISGARH
FLATS STARTS FROM
13.99*
LAKHS
रिसाली क्षेत्र की
प्रथम इंटीग्रेटेड
टाउनशीप
Rera No. : PCGRERA050122001310
LAXMI Sky Life
LAXMI NAGAR, RISALI
अद्भुत,अविश्वसनीय,
अकल्पनीय
1, 2 & 3 BHK Affordable Flats
बुकिंग प्रारंभ
AMENITIES
• Secured Campus With Security Guard and CCTV Camera
• Car Wash Area • Jogging Track • Lush Green Garden
• Plantation Around The Campus For Adequate Greenery
• Sufficient Parking Spaces
• Power Back-up For Common Areas
• Rain Water Harvesting
• Cement Concrete / Paved Internal Roads.
LOCATION ADVANTAGE
• Sector - 9 Hospital - 5Kms
• Durg Railway Station - 7 Kms
• Sector - 10 Market - 2 Kms
• Maa Radheshwari Temple - 3 min. Drive
• Civic Center - 2 Kms
• Bhilai Steel Plant - 1.5 Kms (Maroda Gate)
• Risali Market - 10 min. Drive
• Krishna Talkies Road - 10 min. Drive
• DPS Risali - 10 min. Drive
• Maitri Garden - 2 min. Drive
Sister Concern
ISO : 9001-2015
KanhaJi
SWEETS & RESTAURANT
RISALI, BHILAI
Member of CREDAI
APPROVED
Finance By SBI
Deepak Advertisers
*T&C apply
Office: LAXMI BUILDERS, 83-84,
BSP Market, Risali, Bhilai Ph.: 9174001371
88210 33330, 92291 26555, 93990 21371

छत्तीसगढ़

आदिवासी समाज का उत्थान, न्याय और सम्मान

श्री भूपेश बघेल
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य

- **मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना** के तहत लगभग **50,000 क्लीनिकों** में **14.8 लाख** से अधिक आदिवासी ग्रामीणों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच
- **1.6 लाख** बच्चे कुपोषण और **1 लाख** से अधिक महिलाएं हुईं एनीमिया से मुक्त
- **मलेरिया मुक्त अभियान** की व्यापक सफलता, नीति आयोग एवं यूएनडीपी द्वारा प्रयासों की सराहना, 2018 की तुलना में 2021 में मलेरिया के मामलों में 62.5% की कमी

वर्ष	मलेरिया के मामले
2018	78,717
2021	29,455

शिक्षा

- **स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना** से उत्कृष्ट शिक्षा के समान अवसर
- माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में एक दशक से अधिक समय से बंद पड़े **300 स्कूल फिर से प्रारम्भ**
- **महतारी दुलार योजना** के तहत कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को **निःशुल्क शिक्षा व छात्रवृत्ति**
- जगदलपुर में आकार ले रही राज्यस्तरीय **शहीद गुंडाधुर तीरंदाजी अकादमी**

न्याय

- बस्तर के लोहंडीगुड़ा में अधिग्रहित **4200 एकड़** कृषि भूमि आदिवासी किसानों को वापस
- **51 लाख** से अधिक एकड़ रकबे पर **4,41,000 से अधिक** व्यक्तिगत व **46,000 से अधिक** सामुदायिक वनाधिकार पत्रों का वितरण
- 944 आदिवासियों के खिलाफ दर्ज **718 प्रकरण वापस**, 124 नक्सल प्रकरणों में **218 आदिवासी दोषमुक्त**
- **शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार सामाजिक सुरक्षा योजना** के तहत तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा

आजीविका

- महज 3 सालों में 7 से बढ़कर **61 लघु वनोपजों** की समर्थन मूल्य पर खरीदी
- तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर ₹2,500 से बढ़ाकर ₹**4,000 प्रति मानक बोरा**
- गांवों के उत्पादों की मार्केटिंग हेतु नगर निगमों और नगर पंचायतों में खुलेंगे **सी-मार्ट**
- मुर्गी पालन से रोजगार, अण्डों से कुपोषण को मात

R.O. : 11723/9

सबसे अलग-सबसे आगे, छत्तीसगढ़ सरकार